नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 229
दि. 23.05.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

आसमान से बरसती आग ने झुलसाया हिंदुस्तान 48 डिग्री के पार पहुंचा पारा; देशभर में लू का कहर

इस समय पूरा देश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, और हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि India के कई हिस्से "भट्ठी" की तरह तपते नजर आ रहे हैं। उत्तर से लेकर मध्य और पूर्वी भारत तक तापमान लगातार सामान्य स्तर से कहीं ऊपर बना हुआ है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कई शहरों में पारा 48 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जबकि गर्म हवाओं और कम आर्द्रता ने स्थिति को और भी अधिक खतरनाक बना दिया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार ओडिशा का Balangir 48C तापमान के साथ सबसे गर्म स्थानों में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही बिहार का Sasaram भी 48C के करीब पहुंचकर बेहद गंभीर स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश का Varanasi 47C तापमान के साथ सूची में शामिल प्रमुख गर्म शहरों में रहा, जहां गर्म हवाओं ने लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह केवल कुछ शहरों तक सीमित समस्या नहीं है, बल्कि पूरा उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर दिन के समय सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं, बाजारों में रौनक कम हो गई है और लोग केवल जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। गर्म हवाओं के कारण शरीर से पानी तेजी से निकल रहा है, जिससे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है।

सूचना के अनुसार, दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की एक सूची में 97 शहर India के ही दर्ज किए गए, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। इस सूची में कई राज्यों के

शहर शामिल हैं, जहां तापमान लगातार 44C से 48C के बीच बना हुआ है। ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों में गर्मी का असर सबसे ज्यादा देखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। Uttar Pradesh के मुजफ्फरनगर, अयोध्या, आगरा और वाराणसी जैसे शहरों में तापमान 44C से 47C के बीच दर्ज किया गया है। वहीं हरिद्वार, पटियाला और ग्वालियर जैसे शहर भी भीषण गर्मी की जद में हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर और भरतपुर जैसे इलाके भी लगातार तेज धूप और गर्म हवाओं से प्रभावित हैं।

मौसम विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 22 मई से 27 मई के बीच दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में "भीषण लू" की स्थिति बनी रह सकती है। India Meteorological Department के अनुसार, जब तापमान 45C या उससे अधिक पहुंच जाता है या सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री अधिक होता है, तो उसे लू की स्थिति माना जाता है। इस समय कई क्षेत्रों में यह स्थिति लगातार बनी हुई है। गर्मी के इस प्रकोप का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दिखने लगा है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टरों के अनुसार, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। कई जगहों पर मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है।

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी की मांग तेजी से बढ़ गई है। कुछ इलाकों से जल संकट की खबरें भी सामने आ रही हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पहले से ही पानी की उपलब्धता सीमित है। लोग दिन के समय घरों में कैद रहने को मजबूर हैं और बिजली की खपत भी बढ़ गई है क्योंकि कूलर और एसी पर निर्भरता बढ़ गई है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की भीषण गर्मी जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में गर्मी का पैटर्न तेजी से बदल रहा है, जहां हीटवेव की अवधि लंबी और तीव्र होती जा रही है। पहले जहां कुछ दिनों की गर्मी होती थी, वहीं अब लगातार कई हफ्तों तक अत्यधिक तापमान बना रहता है।

कृषि क्षेत्र पर भी इसका गहरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। खेतों में नमी कम होने से फसलों पर दबाव बढ़ रहा है और कुछ जगहों पर सिंचाई की जरूरत अचानक बढ़ गई है। पशुओं के लिए भी यह मौसम बेहद कठिन साबित हो रहा है। शहरों में यातायात और कामकाजी जीवन पर भी गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है। दोपहर के समय सड़कें खाली हो जा रही हैं और लोग सुबह या शाम के समय ही बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। छोटे दुकानदारों और दिहाड़ी मजदूरों के लिए यह मौसम सबसे कठिन साबित हो रहा है, क्योंकि उनकी आय पर सीधा असर पड़ रहा है।

फिलहाल मौसम विभाग ने लोगों को दिन के समय अनावश्यक बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और धूप से बचने की सलाह दी है। साथ ही यह भी कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक राहत मिलने की संभावना कम है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

कुल मिलाकर, देश इस समय भीषण गर्मी की एक गंभीर लहर से गुजर रहा है, जिसने न केवल मौसम को बल्कि आम जनजीवन, स्वास्थ्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था तक को प्रभावित किया है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे, तो आने वाले दिनों में यह संकट और गहरा सकता है।

NCERT विवाद में सुप्रीम कोर्ट से लेखकों को बड़ी राहत, ब्लैकलिस्टिंग आदेश वापस

Supreme Court of India ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) से जुड़े एक विवाद में बड़ा निर्णय लेते हुए तीन शिक्षाविदों को राहत प्रदान की है। यह मामला कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक में "न्यायपालिका में भ्रष्टाचार" विषयक अध्याय को लेकर उठे विवाद से जुड़ा था, जिसमें तीन विशेषज्ञ लेखकों की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे।

इस मामले में जिन तीन शिक्षाविदों को पहले विवाद का सामना करना पड़ा था, वे हैं प्रोफेसर Michel Danino, Supran Divakar और Alok Prasanna Kumar। इन सभी को लेकर पहले अदालत ने सख्त टिप्पणी की थी और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों द्वारा नियुक्त न किए जाने तक की बात कही गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के निर्देशों में संशोधन करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट से बाहर कर दिया है।

न्यायमूर्ति Suryakant, न्यायमूर्ति Joymalya Bagchi और न्यायमूर्ति Vipul Pancholi की पीठ ने शुक्रवार को यह निर्णय सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 11 मार्च के अपने पहले आदेश में जिन टिप्पणियों के आधार पर विशेषज्ञों पर प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया था, उन्हें अब वापस लिया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी माना कि हालांकि पाठ्यक्रम में शामिल सामग्री को लेकर कुछ आपत्तियां थीं और उसे "अनावश्यक" तथा "अवांछनीय" कहा गया था, लेकिन सरकार ने बाद में सुधारात्मक कदम उठाए हैं। अदालत ने विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया और पाठ्यक्रम में आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि विशेषज्ञों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों और सरकार की ओर से उठाए गए सुधारात्मक कदमों को देखते हुए यह उचित होगा कि पहले दिए गए सख्त निर्देशों को वापस लिया जाए। इसी के साथ कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब इन शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट करने या उनसे संस्थानों के संबंध तोड़ने जैसा निर्देश प्रभावी नहीं रहेगा।

यह मामला उस समय शुरू हुआ था जब NCERT की कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान पुस्तक में न्यायपालिका से जुड़े एक अध्याय को लेकर विवाद खड़ा हुआ। कुछ वर्गों ने इस सामग्री को लेकर आपत्ति जताई थी कि यह विषय प्रस्तुति और भाषा के कारण विवादास्पद हो सकता है। इसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा और सुनवाई के दौरान अदालत ने पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया और विशेषज्ञों की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे।

हालांकि, बाद में स्थिति में बदलाव आया जब सरकार ने पाठ्यक्रम समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की और विशेषज्ञ समिति गठित की। इसके बाद अदालत ने माना कि विवादित सामग्री को सुधारने की दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं, जिससे कठोर आदेशों की आवश्यकता नहीं रह गई है।

शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यह निर्णय अकादमिक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी के बीच संतुलन को दर्शाता है। एक ओर जहां पाठ्यक्रम में शामिल सामग्री की गुणवत्ता और संवेदनशीलता महत्वपूर्ण है, वहीं दूसरी ओर शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को बिना ठोस आधार के दंडात्मक स्थिति में डालना उचित नहीं माना जा सकता।

इस फैसले को अकादमिक जगत में राहत भरे कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि शैक्षिक सामग्री पर बहस और समीक्षा जरूरी है, लेकिन विशेषज्ञों पर स्थायी प्रतिबंध जैसे कठोर कदम अंतिम विकल्प होने चाहिए।

फिलहाल इस निर्णय के बाद तीनों शिक्षाविदों के लिए संस्थानों और शैक्षणिक निकायों के साथ काम करने का मार्ग फिर से खुल गया है। यह मामला एक बार फिर यह सवाल भी उठाता है कि पाठ्यक्रम निर्माण में विचारों की विविधता और संवेदनशीलता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ताकि शिक्षा प्रणाली निष्पक्ष और समावेशी बनी रहे।

बंगाल में मतदाता अपीलों का पहाड़ निपटारा बेहद धीमा; लाखों मामले लंबित

West Bengal में मतदाता सूची संशोधन को लेकर दाखिल की गई अपीलों के निपटारे की गति बेहद धीमी होने से प्रशासनिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। आंकड़ों के अनुसार करीब 25 लाख लोगों ने मतदाता सूची से जुड़े फैसलों के खिलाफ अपील दायर की थी, लेकिन अब तक इनमें से केवल 6,581 मामलों का ही निपटारा हो पाया है। यह कुल मामलों का महज 0.26 प्रतिशत है, जो प्रक्रिया की धीमी रफ्तार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक जिन मामलों का निपटारा हुआ है, उनमें से करीब 61.5 प्रतिशत मामलों में मतदाताओं के नाम फिर से सूची में जोड़ दिए गए हैं। यानी बड़ी संख्या में अपीलकर्ताओं को राहत मिली है। वहीं लगभग 1,267 मामलों में अपील खारिज कर दी गई है। इसके अलावा 1,200 से अधिक मामलों की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है, जिससे पारदर्शिता और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

यह पूरी प्रक्रिया उस समय शुरू हुई जब सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद 20 मार्च को विशेष न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल)

गठित किए गए थे ताकि मतदाता सूची संशोधन से जुड़ी शिकायतों का निपटारा किया जा सके। इस व्यवस्था के तहत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम अपनाए गए।

कोलकाता के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में अब तक 1,777 मामलों का निपटारा हुआ है, जो कुल निपटाए गए मामलों का लगभग 27 प्रतिशत हिस्सा है। इन न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश T. S. Sivagnanam कर रहे थे, जिन्होंने 7 मई को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद प्रक्रिया की गति और प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। सबसे चिंताजनक स्थिति मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में देखी जा रही है। Murshidabad में 6.29 लाख से अधिक अपीलों में से केवल 112 मामलों का निपटारा किया गया है, जबकि Malda में 5.26 लाख से अधिक अपीलों के मुकाबले मात्र 185 मामलों का निपटारा हुआ है। इन दोनों जिलों में लंबित मामलों की भारी संख्या ने पूरी प्रणाली की कार्यक्षमता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर लंबित मामलों का एक प्रमुख कारण प्रशासनिक ढांचे की सीमित क्षमता और न्यायाधिकरणों पर अत्यधिक बोझ है। लाखों अपीलों के बीच सुनवाई की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है, जिससे आम नागरिकों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ रहा है।

आंकड़ों के अनुसार दोनों जिलों में मिलाकर 51,000 से अधिक मामले अभी भी लंबित हैं। यह स्थिति दर्शाती है कि जमीनी स्तर पर मतदाता सूची सुधार की प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। कई मामलों में लोगों को अपने नाम सूची में वापस जुड़वाने के लिए महीनों से इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहे हैं।

राजनीतिक और प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि मतदाता सूची जैसे संवेदनशील मुद्दों पर देरी सीधे तौर पर चुनावी प्रक्रिया और नागरिक अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। खासकर ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां दस्तावेजीकरण और पहुंच पहले से ही चुनौतीपूर्ण है, वहां इस तरह की देरी और जटिलताएं स्थिति को और कठिन बना देती हैं।

हालांकि चुनाव आयोग की ओर से यह दावा किया गया है कि सभी अपीलों का निपटारा चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, लेकिन मौजूदा आंकड़े बताते हैं कि प्रक्रिया अभी शुरुआती स्तर पर ही है और लंबा रास्ता तय किया जाना बाकी है।

फिलहाल यह मामला प्रशासनिक क्षमता, न्यायिक निगरानी और चुनावी सुधारों के बीच संतुलन की आवश्यकता को फिर से उजागर कर रहा है।

पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर 'स्मार्ट बॉर्डर' सुरक्षा, घुसपैठ पर कड़ी नजर की तैयारी

देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था को और आधुनिक बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाने की घोषणा की है। नई योजना के तहत India की सीमाओं, विशेषकर Pakistan और Bangladesh से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर 'स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम' लागू किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सीमा पार से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवैध गतिविधियों पर तकनीक आधारित सख्त निगरानी स्थापित करना है।

इस योजना की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के संस्थापक केएफ रुस्तमजी की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय संरचना और आंतरिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि अवैध घुसपैठ और सीमा पार से होने वाली गतिविधियों को रोकना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा।

नई योजना के तहत सीमा पर ड्रोन, रडार, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, स्मार्ट कैमरे और आधुनिक सेंसर नेटवर्क जैसी तकनीकों को एकीकृत किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि सीमा पर हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी रखी जा सके और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सके। इस प्रणाली को 'स्मार्ट बॉर्डर' नाम दिया गया है, जो पारंपरिक निगरानी व्यवस्था से कहीं अधिक उन्नत मानी जा रही है।

गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले एक वर्ष के भीतर इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्रालय और सीमा सुरक्षा से जुड़े सभी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि तकनीकी ढांचे को तेजी से मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती राज्यों जैसे West Bengal, Assam और Tripura के साथ समन्वय को और मजबूत किया जाएगा, ताकि सीमा सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी न रह जाए।

अमित शाह ने अपने बयान में यह भी कहा कि घुसपैठ और अवैध गतिविधियां केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं हैं, बल्कि यह देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को भी प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति में जनसांख्यिकीय बदलाव से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि को सफल नहीं होने देगी।

उनके अनुसार, सीमावर्ती इलाकों में होने वाली घुसपैठ पर सख्त नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका असर लंबे समय में राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है।

इस परियोजना के साथ ही एक उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिशन शुरू करने की भी घोषणा की गई है। इस मिशन का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या से जुड़े बदलावों की निगरानी करना और सुरक्षा एजेंसियों को आवश्यक डेटा और विश्लेषण उपलब्ध कराना होगा। सरकार का मानना है कि इससे नीति निर्धारण और सुरक्षा रणनीति को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। सीमा सुरक्षा बल Border Security Force की भूमिका को इस नई व्यवस्था में और अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। वर्तमान में पाकिस्तान सीमा पर लगभग 93 प्रतिशत और बांग्लादेश सीमा पर लगभग 80 प्रतिशत बाड़बंदी का काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ड्रोन के जरिए हथियारों, नशीले पदार्थों और नकली मुद्रा की तस्करी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। नई तकनीकी व्यवस्था इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सरकार का मानना है कि आधुनिक युद्ध और सुरक्षा चुनौतियों के इस दौर में केवल भौतिक बाड़बंदी पर्याप्त नहीं है। इसलिए डिजिटल निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिस्टम को भी सीमा सुरक्षा का हिस्सा बनाया जा रहा है। इस प्रणाली के लागू होने के बाद सीमा पर किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पहचान कुछ ही सेकंड में संभव हो सकेगी, जिससे सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया समय में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की तकनीक आधारित सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के कई विकसित देशों में पहले से लागू है। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों में सीमा सुरक्षा को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रोन और सैटेलाइट आधारित निगरानी अब आधुनिक सीमा सुरक्षा का अहम हिस्सा बनती जा रही है। हालांकि, इस योजना को लागू करना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत की सीमाएं भौगोलिक रूप से अत्यंत विविध और कई जगहों पर कठिन परिस्थितियों वाली हैं। कुछ इलाके नदी, दलदली जमीन और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे हुए हैं, जहां तकनीकी उपकरणों को प्रभावी रूप से स्थापित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके बावजूद सरकार का दावा है कि चरणबद्ध तरीके से इस व्यवस्था को हर संवेदनशील क्षेत्र में लागू किया जाएगा।

राजनीतिक स्तर पर इस घोषणा को सरकार की मजबूत सुरक्षा नीति के रूप में देखा जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को नई मजबूती देगा, जबकि आलोचकों का मानना है कि इसके क्रियान्वयन और मानवाधिकार से जुड़े पहलुओं पर भी ध्यान देना जरूरी होगा।

फिलहाल 'स्मार्ट बॉर्डर' योजना को भारत की सीमा सुरक्षा में एक बड़े तकनीकी परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में यह स्पष्ट होगा कि यह व्यवस्था जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है और क्या यह देश की सीमाओं को पहले से अधिक सुरक्षित बनाने में सफल हो पाती है।

संपादकीय

आपदा मानकर तैयारी बढ़ाने की जरूरत

हाल के दिनों में आसमान से बरसती आग से देश में जन-जीवन बुरी तरह झुलस रहा है। रोज तापमान बढ़ने के नये रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। ये असहनीय तापमान केवल स्वास्थ्य की चुनौती मात्र नहीं है, बल्कि एक आर्थिक संकट भी है। देश में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक भीषण गर्मी में काम करने को मजबूर हैं। यदि वे ऐसा न करें तो उनके सामने आजीविका का संकट पैदा हो जाता है। स्कूल-कालेज तो लू के दौरान बंद किए जा सकते हैं, सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों में काम के घंटों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर व निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को तो तपती दोपहरी व लू के बीच काम करने को मजबूर होना पड़ता है। दरअसल, लू की मार जहां शारीरिक है, वहीं आर्थिक भी। लगातार बढ़ते तापमान से लोगों की आजीविका और श्रम उत्पादकता पर बुरा असर पड़ रहा है। इस संकट को हाल के दिनों में हुई ईंधन की कीमतों की वृद्धि और महंगाई ने और बढ़ा दिया है। लोगों को सीमित संसाधनों में जीवन यापन को मजबूर होना पड़ रहा है। विडंबना यह है कि इस संकट का सबसे घातक प्रभाव उस तबके को सहन करना पड़ता है जो 'रोज कुंआ खोदकर पानी पीने' को बाध्य है। एक दिन की कमाई से ही रात को उसके घर का चूल्हा जलता है। लू के निशाने पर वे अनौपचारिक श्रमिक हैं जो भारतीय आर्थिकी की रीढ़ है। सही मायनों में लू के खिलाफ लड़ाई को अब केवल एक मौसमी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या ही नहीं माना जा सकता है। धीरे-धीरे यह एक गंभीर आर्थिक चुनौती भी बनी है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस बाबत चेताते रहे हैं। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया था कि लू से उपजे हालात से भारत को सौ अरब डॉलर का नुकसान हुआ था।

इससे पहले वर्ष 2022 में विश्व बैंक ने चेतावनी दी थी कि भारत का तीन-चौथाई श्रमिक वर्ग लू से प्रभावित क्षेत्रों में काम करने को मजबूर है। अनुमान है कि लू के तनाव के कारण होने वाली विश्वव्यापी नौकरियों की कमी में भारत की हिस्सेदारी आधी हो सकती है। दरअसल, भारत में सबसे अधिक जोखिम वाले समूहों में निर्माण श्रमिक, खेतिहर श्रमिक, किसान, स्ट्रीट वेंडर और डिलीवरी एजेंट शामिल हैं। हालांकि, समय-समय पर केंद्र व राज्य सरकारों ने कार्य समय का पुनर्निधारण, छायादार विश्राम क्षेत्र बनाने, जलपान सुविधा, सुरक्षात्मक कपड़े और स्वास्थ्य निगरानी को लेकर एडवाइजरी जारी की है,लेकिन फिर भी संकट के दायरे को देखते हुए ये उपाय नाकाफी हैं। देखा जाए तो फिलहाल भारत में गर्मी के संकट से मुकाबले के लिये बनायी गई योजनाएं काफी हद तक अस्थायी रूप से राहत देने वाली हैं। वक्त की मांग है कि भीषण गर्मी वाले महीनों के लिये तत्काल व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया जाए। ऐसा तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो लू चलने के दौरान सुरक्षित कार्य परिस्थितियों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान करे। इस साल के आरंभ में वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि भीषण गर्मी के दौरान चलने वाली लू को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिसूचित आपदाओं की सूची में शामिल किया जाए। निस्संदेह, इस वर्गीकरण से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से मिलने वाले धन का उपयोग लोगों को राहत और सहायता प्रदान करने में मदद देगा। इसके अलावा लू के दौरान कई अन्य नकारात्मक प्रभाव भी देखने में आते हैं। मसलन इस समय बिजली व पानी की खपत अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। इससे निबटने के लिये मजबूत और सक्रिय तंत्र विकसित करने की जरूरत है। निर्विवाद रूप से देश के नीति-निर्माताओं और अन्य हितधारकों के सामने इस संकट से मुकाबले के लिये स्पष्ट विकल्प मौजूद हैं। केंद्र व राज्य सरकारों को चाहिए कि समय रहते निर्णायक रूप से अनुकूलन का तंत्र विकसित करें। यदि समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया तो भविष्य में अधिक मानवीय क्षति व आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है।

Trump-Netanyahu के बीच क्यों हुआ झगड़ा, ईरान को कैसे इससे मिल गया बड़ा मौका?

> "ट्रंप ने कैमरे पर बेबाकी से कह दिया बेंजामिन नेतन्याहू वही करेंगे, जो मैं उनसे चाहूंगा। नेतन्याहू का मानना है कि ट्रंप का यह यू-टर्न ईरान को परमाणु हथियार बनाने और मिसाइलें रीग्रुप करने का समय दे रहा है। फिलहाल, इस 'पावर स्ट्रगल' ने यह साफ कर दिया है कि ईरान वॉर के अगले कदम को लेकर वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच सबकुछ ठीक नहीं है।

ईरान को घुटनों पर लाने के लिए जिस अमेरिका और इजराइल ने कंधे से कंधा मिलाकर बम बरसाए थे, आज वही दोनों महाशक्तियां आपस में भिड़ गई हैं। वजह कोई जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि वही 'ईरान' है जिस पर दोनों मिलकर फतह पाना चाहते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 19 मई की रात हुई एक सीक्रेट फोन कॉल ने दोनों देशों के रिश्तों में छिपे तनाव को दुनिया के सामने ला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह बातचीत इतनी तीखी थी कि इसके बाद नेतन्याहू गुस्से से तमतमा उठे थे। अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स सीएनएन और एग्जिओस ने खुफिया सूत्रों के हवाले से इस महा-तनाव की इनसाइड स्टोरी पब्लिश की है। सूत्रों के मुताबिक, करीब एक घंटे चली इस मुश्किल कॉल के बाद नेतन्याहू का पारा सातवें आसमान पर था। अमेरिकी अधिकारियों ने तंज कसते हुए कहा कि कॉल के बाद बीबी (नेतन्याहू) के बालों में आग लग गई थी। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के सैन्य ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दोबारा भीषण हमले किए जाएं ताकि वह संभल न सके। वहीं, ट्रंप ने ऐन वक्त पर हमलों को रोक दिया है। वह कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे खाड़ी मध्यस्थों द्वारा तैयार 'लेटर ऑफ इंटेंट' को मौका देना चाहते हैं, जिसके तहत 30 दिनों के लिए युद्ध विराम और बातचीत का रास्ता खुल सके। इस तनातनी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने एक ऐसा बयान दे दिया, जिसने इजराइल की संप्रभुता और नेतन्याहू के ईगो पर गहरी चोट की है। ट्रंप ने कैमरे पर बेबाकी से कह दिया बेंजामिन नेतन्याहू वही करेंगे, जो मैं उनसे चाहूंगा। नेतन्याहू का मानना है कि ट्रंप का यह यू-टर्न ईरान को परमाणु हथियार बनाने और मिसाइलें रीग्रुप करने का समय दे रहा है। फिलहाल,

इस 'पावर स्ट्रगल' ने यह साफ कर दिया है कि ईरान वॉर के अगले कदम को लेकर वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच सबकुछ ठीक नहीं है। 19 मई 2026 की तारीख वाइट हाउस और यरूशलम फोन लाइन से जुड़े। करीब 1 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की बात हुई। एग्जिओस की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू इस कॉल के दौरान परेशान नजर आए। बहुत हद तक इसका कारण है 17 मई का दिन। इस दिन डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को भरोसा दिलाया था कि अमेरिका मंगलवार यानी 19 मई को ईरान पर नए और घातक हमलों की शुरुआत करेगा। इजराइल इसी की उम्मीद में बैठा था। लेकिन 24 घंटे के भीतर ट्रंप ने यू टर्न ले लिया क्योंकि कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी ने ऐसे हमले ना करने का अनुरोध किया था। ऐसे में नेतयाहू ने कहा कि हमलों को टालना एक बहुत बड़ी गलती है और इससे केवल ईरान को अपनी सैन्य ताकत फिर से संगठित करने का समय मिलेगा। एग्जिओस ने एक अमेरिकी सूत्र के हवाले से दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत की जानकारी छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि मीडिएटर एक लेटर ऑफ इंटेंट पर काम कर रहे हैं जिस पर अमेरिका और ईरान दोनों साइन करेंगे। जिसका मकसद युद्ध को औपचारिक रूप से खत्म करना है। साथ ही इसके जरिए ईरान के एटम प्रोग्राम और स्टेट ऑफ फोरमच को खोलने जैसे मुद्दों पर 30 दिनों की बातचीत शुरू होगी।

दो इजराइली सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि दोनों नेता ईरान को लेकर आगे के प्लान पर एकमत नहीं हैं। सोर्सेस का कहना है कि वाशिंगटन में इजराइल के राजदूत ने अमेरिकी सांसदों को जानकारी दी थी कि नेतन्या इस बातचीत को लेकर चिंतित थे। हालांकि दूतावास के एक प्रवक्ता ने एक्सियोस को इस बात से इंकार किया और कहा राजदूत निजी बातचीत पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर दोबारा हमला करने का प्लान बनाया था। इस बार होने वाले ऑपरेशन को नया नाम दिया गया था। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देश ईरान के खिलाफ ऑपरेशन स्लेज़ हैमर शुरू करने वाले थे। इसी प्लानिंग की वजह से नेतयाओं को लग रहा था कि वह अपना एकमेव लक्ष्य हासिल कर लेंगे। यानी ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ना आए तो किरदार का नाम ट्रंप का आएगा। ट्रंप ने ऐन वक्त पर ऑपरेशन स्लेज़ हैमर को टाल दिया। ट्रंप ने 18 मई को सोशल मीडिया पर लिखा कि वो ईरान पर 1 घंटे में ही हमला कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे और डिप्लोमेसी के लिए वक्त देंगे। बस यह ट्विस्ट नेऊ के लिए टेंशन बन गया। क्योंकि जिन ट्रंप के बारे में कहा जाता था कि ईरान पर हुए हमले में इजराइल ने जैसा चाहा अमेरिका ने वैसा ही बिहेव किया।

ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, जबकि तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए मिले नए अमेरिकी प्रस्ताव की समीक्षा शुरू कर दी है। ईरान ने अपनी शर्तों में विदेशों में फसी संपत्तियों की रिहाई और ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी खत्म करने की मांग दोहराई है।

ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने निर्देश दिया है कि देश का हथियार-ग्रेड समृद्ध यूरेनियम किसी भी हालत में विदेश नहीं भेजा जाएगा। दो वरिष्ठ ईरानी सूत्रों के हवाले से यह दावा सामने आया है। इस रुख से अमेरिका-ईरान के बीच चल - रही शांति वार्ता में नया पेंच फंस सकता है। इसकी वजह अमेरिका-इजराइल की प्रमुख मांगों में ईरान के यूरेनियम को दूसरे देश में भेजना शामिल है।

अमेरिकी खुफिया आकलन के मुताबिक ईरान सैन्य क्षमता तेजी से खड़ी कर रहा है। युद्धविराम के दौरान उसने ड्रोन प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। - अनुमान है कि वह 6 महीने में ड्रोन हमले की - क्षमता बहाल कर लेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि -ईरान नष्ट हुई मिसाइल साइट्स, लॉन्चर्स व हथियार उत्पादन क्षमता को भी जल्द तैयार कर लेगा। अमेरिका ने अपना रवैया बदल दिया है। नेतन्याहू के गुस्से की एक बड़ी वजह यह भी थी कि इजराइली खुफिया एजेंसी मोसाद और सैन्य अधिकारियों का मानना है कि ईरान युद्ध के दौरान बंद किए गए अपने मिसाइल ठिकानों को फिर से सक्रिय कर चुका है। इजराइल का मानना है कि इस वक्त ईरान पर हमला ना करना उसे परमाणु बम बनाने की खुली छूट देने जैसा है। उधर ट्रंप और नेतन्या की बातचीत को लेकर मचे बवाल के बीच ईरान का भी जवाब आ गया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने एक्स पर लिखा ईरान ने हमेशा अपने वादे को निभाया है। युद्ध को टालने की हर संभव कोशिश की है। हमारी ओर से रास्ते खुले हैं लेकिन दबाव डालकर ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर करना सिर्फ एक भ्रम है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गाड्र्स आईआरजीसी ने और भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा अगर अमेरिका ने फिर से हमला किया तो वे खाड़ी देशों के तेल की आपूर्ति को सालों के लिए काट देंगे। धमकी यह भी दी कि अगला हमला किसी क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो ट्रंप बातचीत की राह पर हैं। उनके पार्टनर नेतन्या इस बात से निराश हैं। इन दोनों के बीच टेंशन का यह कोई पहला मौका नहीं है। याद कीजिए जंग के दौरान ईरान के साउथ पाट्र्स गैस क्षेत्र पर एक बड़ा हमला हुआ। रिपोट्र्स आई कि यह हमला इजराइल ने किया। ट्रंप इस हमले की वजह से इजराइल पर भड़क गए तब ट्रंप ने कहा था कि इजराइल ने अकेले कारवाई की है और वाशिंगटन को इस बारे में पहले से कुछ नहीं पता था। ट्रंप ने यह भी कहा था हमने ईरान के साउथ पाट्र्स गैस क्षेत्र इजराइल के हमले का विरोध किया और बेंजामिन नेतन्या से सीधे तौर पर ऐसा ना करने का आग्रह किया था। इसके अलावा ट्रंप ने चेतावनी भी दी थी कि हम ऐसे कामों के लिए मना करते हैं वो नहीं मानते और हमें काम पसंद नहीं आता तो हम आगे काम नहीं करते हैं।

प्रेरणा

शब्दों से बड़ी कोई दौलत नहीं

मनुष्य के जीवन में कई ऐसी चीजें होती हैं, जो दिखाई नहीं देतीं, लेकिन वही उसके व्यक्तित्व की असली पहचान बनती हैं। धन, पद, प्रसिद्धि और शक्ति समय के साथ बदल जाते हैं, परंतु व्यक्ति का चरित्र और उसके शब्दों की विश्वसनीयता हमेशा उसके साथ रहती है। संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, जिनके कहे हुए शब्द पत्थर की लकीर बन जाते हैं। जो व्यक्ति अपने वचन का सम्मान करता है, वही दूसरों के दिलों में सम्मान प्राप्त करता है। मित्रता भी केवल साथ समय बिताने का नाम नहीं, बल्कि एक-दूसरे के विश्वास और भावनाओं की रक्षा करने का नाम है। जब कोई व्यक्ति अपने छोटे-से-छोटे वादे को भी गंभीरता से निभाता है, तभी वह वास्तव में महान कहलाने योग्य बनता है। महान वैज्ञानिक Albert Einstein का जीवन केवल विज्ञान की उपलब्धियों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके व्यवहार में भी ऐसी मानवता थी, जो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है। आइंस्टीन की मित्रता प्रसिद्ध संगीतकार Leopold Godowsky के साथ अत्यंत गहरी थी। दोनों अलग-अलग क्षेत्रों के महान व्यक्तित्व थे, लेकिन उनकी आत्मीयता में कोई दूरी नहीं थी। वे एक-दूसरे की प्रतिभा का सम्मान करते थे और एक-दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते थे। गोदोव्सिकी केवल एक महान संगीतकार ही नहीं थे, बल्कि अत्यंत संवेदनशील और विनम्र व्यक्ति भी थे। उनकी बातचीत में हमेशा अपनापन झलकता था। एक दिन उन्होंने मुस्कराते हुए आइंस्टीन से कहा कि उनका नाई उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। वह नाई आइंस्टीन को केवल एक वैज्ञानिक नहीं, बल्कि संसार के सबसे असाधारण मनुष्यों में से एक मानता था। उसके मन में वर्षों से यह इच्छा थी कि वह एक बार आइंस्टीन से मिल सके। यह सुनकर आइंस्टीन ने तुरंत कहा कि वे उसी समय उसके साथ चल पड़ते, लेकिन उस समय वे अत्यंत व्यस्त थे। उन्होंने सहजता से नाई का पता लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने यह भी कहा कि अवसर मिलते ही वे उससे मिलने अवश्य आएंगे। यह एक सामान्य-सी बात थी, जैसी बातें लोग अक्सर औपचारिकता में कह देते हैं। अधिकांश लोग ऐसी बातों को भूल जाते हैं, क्योंकि जीवन की भागदौड़ में उन्हें छोटी बातें महत्वहीन लगने लगती हैं। लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं, जिनके लिए हर शब्द का महत्व होता है। आइंस्टीन उन्हीं लोगों में से थे। समय बीतता गया। आइंस्टीन का जीवन पहले से अधिक व्यस्त होता चला गया। दुनिया भर के विश्वविद्यालय उन्हें बुलाते थे। वैज्ञानिक सम्मेलन, शोध और यात्राएं उनके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। उनके पास आराम करने तक का समय नहीं होता था। लोग उन्हें अक्सर "भुलक्कड़ वैज्ञानिक" कहते थे, क्योंकि वे कई बार अपनी चीजें भूल जाया करते थे। कभी जुराबें पहनना भूल जाते, कभी चाबियां कहीं रखकर भूल जाते। उनकी इस आदत के कई किस्से प्रसिद्ध थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जो व्यक्ति दैनिक जीवन की साधारण बातें भूल जाता था, उसने एक साधारण नाई से मिलने का वादा कभी नहीं भुलाया। वर्षों बीत गए। परिस्थितियां बदलती रहीं। फिर एक दिन आइंस्टीन को यह दुखद समाचार मिला कि उनके प्रिय मित्र गोदोव्सिकी अब इस संसार में नहीं रहे। यह समाचार उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। एक सच्चे मित्र को खो देना जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक होता है। आइंस्टीन तुरंत न्यूयॉर्क पहुंचे। वहां उन्होंने अपने मित्र के परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। वे अपने मित्र की स्मृतियों में डूबे हुए थे। हर ओर उदासी का वातावरण था। लेकिन उसी दुख के बीच अचानक उन्हें वर्षों पहले किया गया अपना वादा याद आया। उन्होंने सोचा कि जिस मित्र ने कभी उनसे अपने नाई की इच्छा बताई थी, उसके प्रति उनका दायित्व अभी अधूरा है। उन्होंने तुरंत उस पुराने पते को निकाला, जिसे वे वर्षों से संभालकर रखे हुए थे। इसके बाद वे सीधे उस छोटी-सी दुकान पर पहुंचे, जहां शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक कभी आएगा। उस समय नाई अपनी दुकान में सामान्य दिनों की तरह काम कर रहा था। वर्षों पहले की वह बात अब उसकी स्मृति से लगभग मिट चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आइंस्टीन वास्तव में उससे मिलने आएंगे। उसके लिए वह केवल एक सपना था। अचानक जब दुकान का दरवाजा खुला और उसने सामने आइंस्टीन को खड़े देखा, तो वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास और खुशी एक साथ भर उठी। कुछ क्षणों तक वह समझ ही नहीं पाया कि यह सच है या सपना। उसके हाथ कांपने लगे। आंखें नम हो गईं। वह कुछ बोल नहीं सका। संसार के सबसे सम्मानित वैज्ञानिक उसके सामने खड़े थे, और वह भी केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने वर्षों पहले किया हुआ अपना वादा निभाना जरूरी समझा। उस क्षण नाई के लिए यह केवल एक मुलाकात नहीं थी; यह उसके अस्तित्व का सम्मान था। उसे यह एहसास हुआ कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जिनके लिए एक साधारण इंसान की भावनाएं भी मूल्य रखती हैं।

आइंस्टीन ने वहां बैठकर उससे आत्मीयता से बातचीत की। उन्होंने उसे यह महसूस नहीं होने दिया कि उनके बीच कोई ऊंच-नीच का अंतर है। यही किसी महान व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है। जो जितना बड़ा होता है, वह उतना ही विनम्र होता है। वास्तव में महानता वही है, जिसमें व्यक्ति अपने से छोटे लोगों को भी सम्मान देना जानता हो। आज के समय में यह घटना और भी अधिक प्रासंगिक लगती है। आधुनिक जीवन में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि संबंधों की गर्माहट धीरे-धीरे कम होती जा रही है। लोग वादे तो कर देते हैं, लेकिन निभाने की कोशिश नहीं करते। शब्दों की कीमत कम होती जा रही है। कई बार लोग केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाते हैं और समय आने पर उन्हें भूल जाते हैं। ऐसे दौर में आइंस्टीन का यह व्यवहार हमें याद दिलाता है कि सच्चा सम्मान केवल उपलब्धियों से नहीं मिलता, बल्कि संवेदनशीलता और विश्वसनीयता से मिलता है। एक छोटा-सा वादा निभाकर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि इंसान की असली महानता उसके व्यवहार में होती है। जिसने दूसरों की भावनाओं को समझना सीख लिया, वही वास्तव में जीवन का अर्थ समझ पाया। यदि कोई व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान नहीं कर सकता, तो उसकी सारी सफलताएं अधूरी हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने वचनों के प्रति ईमानदार रहता है, वह बिना किसी पद या प्रसिद्धि के भी लोगों के दिलों में अमर हो जाता है। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता। एक साधारण नाई की इच्छा को महत्व देकर आइंस्टीन ने मानवता का सबसे सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने दिखाया कि प्रेम, सम्मान और विश्वास किसी भी पुरस्कार से अधिक मूल्यवान होते हैं। जीवन में यदि हम अपने शब्दों को सच्चाई से निभाना सीख जाएं, तो हमारे संबंध कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। यही गुण मनुष्य को महान बनाता है और यही कारण है कि आज भी आइंस्टीन केवल एक महान वैज्ञानिक नहीं, बल्कि एक महान इंसान के रूप में पूरी दुनिया में आदर के साथ याद किए जाते हैं।

भारत में जानलेवा हुई गर्मी के साइड इफेक्ट्स समझिए, इसके कारण और बचाव के उपाय जानिए

हमारे देश का राजनीतिक तापमान तो वर्षपर्यंत उच्च रहता आया है और चुनावी इलाकों में इसके वैचारिक हीट स्ट्रोक से सिस्टम का झुलसना स्वाभाविक माना जाता है। लेकिन जब मई-जून के महीने में मौसमी तापमान जानलेवा स्तर तक खतरनाक रूप से चढ़ता जाता है तो लोग बाग परेशान हो उठते हैं। फिर अपनी राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गलतियों पर पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि विकास के नाम पर आधुनिक भारतीय सभ्यता विनाश की ओर बढ़ती चली जा रही है और पश्चिमी शिक्षा प्राप्त हमारे हुक्मरान तमाशबीन बने बैठे हैं, क्योंकि हरेक आपदा को अवसरों में बदलकर अपनी कमाई बढ़ाने का धंधा उन्होंने सीख लिया है। बेशक अपवाद भी होंगे, लेकिन अल्पमत में, जिनकी लोकतंत्र में कम कद्र होती आई है। वहीं, भारत में बढ़ती खतरनाक गर्मी केवल "मौसमी बदलाव" नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन, तेजी से शहरीकरण, जंगलों की कटाई और प्रदूषण का संयुक्त परिणाम बन चुकी है। हाल के वर्षों में उत्तर भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य भारत में 46C–48C तक तापमान दर्ज हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश का एक बड़ा हिस्सा इस समय भट्ठी बना हुआ है। हमारे शहर हीट आइलैंड में तब्दील होते जा रहे हैं। उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक, ज्यादातर शहरों में औसत तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। कहीं कहीं तो पिछले 14-15 वर्षों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कोढ़ में खाज यह कि फिलहाल राहत के संकेत नहीं है, क्योंकि अल-नीनो की वजह से मौसम आगे और कड़ी परीक्षा ले सकता है।

अलबत्ता आप मानें या न मानें, लेकिन गर्मी की बढ़ती प्रवृति में भविष्य के लिए सबसे बड़ा संदेश छिपा हुआ है। वह यह कि यदि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन नहीं बनाया गया तो भारत में गर्मी केवल असुविधा नहीं बल्कि "राष्ट्रीय स्वास्थ्य और आर्थिक संकट" बन सकती है। लिहाजा, आने वाले वर्षों में जल संरक्षण, हरित विकास और स्वच्छ ऊर्जा ही सबसे बड़े समाधान होंगे।

विभिन्न अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सीजन 27 अप्रैल और 19 मई दो ऐसे दिन रहे, जब धरती के सबसे ज्यादा गर्म 50 शहरों में सभी भारत के थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की रिपोर्ट हमें चेताती है कि देश के 50% से ज्यादा शहरों में भीषण गर्मी का खतरा 'अधिक' से लेकर 'बेहद अधिक' के स्तर तक पहुंच चुका है। और तो और, साल 2015 से 2020 के दरम्यान लू वाले दिनों का औसत 7.4 दिन से बढ़कर 32.2 दिन हो गया है, और यह लगातार बढ़ रहा है। इसका गहरा दुष्प्रभाव हमारी सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ने के आसार प्रबल हैं।

हमारे शहरों पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि वो अंधाधुंध विकास की होड़ में अपनी हरियाली उजाड़कर उन्हें कंक्रीट के जंगलों में तब्दील करते जा रहे हैं। लिहाजा, भारत में गर्मी अब हर साल एक नया रेकॉर्ड बना रही है। चिंताजनक बात यह है कि दिन तो तपते ही हैं, अब रातें भी तपने लगी हैं और राहत देने वाली नहीं रहीं। इस 20 मई को दिल्ली ने मई महीने में 13 साल की सबसे गर्म रात देखी, जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा। 21 मई को स्थिति उससे भी ज्यादा बुरी हुई।इस प्रकार से हाल के बरसों में हीटवेव की तीव्रता, उसका समय और सीमा अभूतपूर्व रूप से बढ़े हैं। इससे शहरों पर संकट ज्यादा है, जो घटती हरियाली, बढ़ते कंक्रीट स्ट्रक्चर और प्रदूषण की वजह से अर्बन हीट आईलैंड इफेक्ट' झेल रहे हैं।

इससे हमारे कामकाज पर भी नकारात्मक असर पड़ चुका है, क्योंकि मौसम की यह मार दोतरफा है- सेहत और अर्थव्यवस्था दोनों पर पड़ चुकी है। नैशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक, 2025 में हीट स्ट्रोक के सात हजार से ज्यादा सस्पेक्टेड केस सामने आए थे। हालांकि माना जाता है कि भारत में हीट स्ट्रोक और उससे होने वाली मौतों का सही आंकड़ा रिपोर्ट नहीं हो पाता। क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी मौसम का सीधा वार झेलती रहती है। इनमें गिग वर्कर्स, दिहाड़ी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह भी शामिल हैं। चूंकि घर बैठने से न इनका काम चलेगा और न अपने देश का। लिहाजा इस मौसम में ये सबसे ज्यादा जोखिम में ये लोग ही होते हैं। किसान और मजदूर भी इन्हीं जैसे होते हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते है, जैसे सार्वजनिक शेल्टर, पेयजल की व्यवस्था और जहां संभव हो वहां काम के घंटों और चरित्र में बदलाव। इसे गंभीर चेतावनी के रूप में लिया जा सकता है। चूंकि बढ़ती हुई गर्मी से हमारी आपकी कार्यक्षमता पर सीधा असर पड़ता है, काम के घंटे कम होते हैं और प्रॉडक्टिविटी भी घट जाती है। लिहाजा यह बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। एक आकलन के मुताबिक, यदि यही हाल रहा तो 2030 तक गर्मी की वजह से भारत की जीडीपी का 4.5 प्रतिशत प्रभावित होगा। ये सारे आंकड़े एक गंभीर चेतावनी हैं। चूंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम के और बिगड़ने की आशंका है, इसलिए बेहतर रहेगा अगर हमलोग अपनी तैयारी पहले से कर लें। भारत में खतरनाक गर्मी बढ़ने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं- पहला, जलवायु परिवर्तनः धरती का औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार मानव गतिविधियों से पैदा हुई ग्लोबल वार्मिंग ने भारत में हीटवेव को अधिक लंबा और तीव्र बना दिया है।

अभियान

नौतपा में जल सेवा का पुण्य, सूर्य कृपा से भर उठता है घर-आंगन

भारतीय सनातन परंपरा में प्रकृति को केवल मौसम का परिवर्तन नहीं माना गया, बल्कि उसे ईश्वर की लीला और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्वरूप समझा गया है। वर्ष का प्रत्येक कालखंड अपने भीतर कोई न कोई आध्यात्मिक संदेश लेकर आता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला नौतपा भी ऐसा ही एक विशेष समय माना जाता है। जब सूर्य अपनी प्रखरता के चरम पर पहुंचते हैं, तब धरती तपने लगती है, हवाएं अग्नि जैसी प्रतीत होती हैं और मनुष्य से लेकर पशु-पक्षी तक जल की तलाश में व्याकुल हो उठते हैं। परंतु ऋषि-मुनियों ने इस कठिन समय को केवल गर्मी का दौर नहीं माना, बल्कि इसे तप, सेवा, संयम और आध्यात्मिक जागरण का अवसर बताया। मान्यता है कि इन नौ दिनों में सूर्य देव की किरणें पृथ्वी पर विशेष प्रभाव डालती हैं और यदि मनुष्य श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक संकल्प के साथ कुछ छोटे-छोटे उपाय करे, तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खुलने लगता है।

सनातन धर्म में जल को जीवन का आधार माना गया है। जल केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि यह मन और आत्मा को भी शांति देता है। वेदों में जल को देवता स्वरूप कहा गया है। कहा जाता है कि जहां शुद्ध जल का सम्मान होता है, वहां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। यही कारण है कि नौतपा के दिनों में घर की उत्तर-पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में जल से भरा पात्र रखने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। वास्तु शास्त्र में ईशान कोण को देवताओं का स्थान माना गया है। यह दिशा भगवान शिव, विष्णु और गुरु तत्व से जुड़ी मानी जाती है। जब इस दिशा में मिट्टी का घड़ा, तांबे का कलश या स्वच्छ जल से भरा पात्र रखा जाता है, तो माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होने लगती है और वातावरण में दिव्यता का संचार होता है।

भक्तिभाव से किए गए छोटे उपाय भी कभी-कभी जीवन में बड़े परिवर्तन ला देते हैं। यदि नौतपा के दौरान मिट्टी के घड़े में स्वच्छ जल भरकर उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियां, तुलसी दल या कपूर की हल्की सुगंध डाल दी जाए, तो वह केवल एक पात्र नहीं रहता, बल्कि घर में शांति और सात्विकता का केंद्र बन जाता है। मान्यता है कि इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव कम होता है और घर का वातावरण शांत और आनंदमय बना रहता है। पुराने लोग कहते थे कि जहां जल का सम्मान होता है, वहां कलह और अशांति अधिक समय तक टिक नहीं पाती।

नौतपा के इन दिनों में सूर्य उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने और तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य देने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। जब उगते हुए सूर्य को श्रद्धा से जल अर्पित किया जाता है, तब जल की धारा से होकर आने वाली सूर्य किरणें मनुष्य के शरीर और मन पर अद्भुत प्रभाव डालती हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, तेज, आत्मविश्वास और राजसत्ता का कारक माना गया है। इसलिए नौतपा के दिनों में सूर्य देव की आराधना करने से व्यक्ति के भीतर नई ऊर्जा का संचार होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देता है, उसके जीवन में निराशा धीरे-धीरे समाप्त होने लगती है और आत्मबल बढ़ने लगता है।

भक्ति में सबसे बड़ा महत्व भावना का होता है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा से सूर्य देव के सामने खड़ा होकर केवल इतना कह दे कि "हे प्रभु, मेरे जीवन से अंधकार दूर कर दीजिए," तो उसकी प्रार्थना भी व्यर्थ नहीं जाती। नौतपा आत्मशुद्धि का समय माना गया है। यह वह काल होता है जब प्रकृति स्वयं तपस्या कर रही होती है। धरती तप रही होती है, पेड़-पौधे गर्मी सह रहे होते हैं, पक्षी जल के लिए भटक रहे होते हैं। ऐसे समय में यदि मनुष्य सेवा और दया का भाव अपनाता है, तो उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है।

शास्त्रों में कहा गया है कि नौतपा के दौरान प्यासे को जल पिलाना सौ यज्ञों के बराबर फल देता है। यही कारण है कि पुराने समय में गांवों और नगरों में लोग राहगीरों के लिए प्याऊ लगवाते थे। मिट्टी के घड़ों में ठंडा पानी भरकर रखा जाता था, ताकि कोई भी प्यासा व्यक्ति वहां आकर जल ग्रहण कर सके। यह केवल सामाजिक सेवा नहीं थी, बल्कि इसे ईश्वर की पूजा माना जाता था। आज भी यदि कोई व्यक्ति इन दिनों में गरीबों, मजदूरों, पशु-पक्षियों या राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करता है, तो वह वास्तव में धर्म का पालन करता है।

नौतपा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में अनुशासन कितना आवश्यक है। इन दिनों में सात्विक भोजन, संयमित दिनचर्या और मन की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन नौ दिनों में क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, उसके जीवन में मानसिक शांति बनी रहती है। घर में साफ-सफाई रखना भी अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से मुख्य द्वार के आसपास गंदगी, टूटे सामान या अव्यवस्था को अशुभ माना गया है। मान्यता है कि जहां स्वच्छता होती है, वहां देवी लक्ष्मी का आगमन होता है।

भारतीय संस्कृति में तुलसी का विशेष स्थान है। नौतपा के दौरान यदि घर के आंगन या पूजा स्थल में तुलसी के पौधे को नियमित जल अर्पित किया जाए और दीपक जलाया जाए, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। उसकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र और सात्विक हो जाता है। कई लोग नौतपा में शाम के समय घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और सूर्य देव की आरती भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में रोग, भय और दरिद्रता का प्रभाव कम होता है।

नौतपा केवल बाहरी ताप नहीं, बल्कि भीतर की तपस्या का भी प्रतीक है। जैसे सूर्य अपनी पूरी शक्ति से चमकते हैं, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर की कमजोरियों को जलाकर आत्मबल को मजबूत करना चाहिए। यह समय हमें याद दिलाता है कि कठिन परिस्थितियां हमेशा विनाश नहीं लातीं, कई बार वे आत्मजागरण का अवसर भी बनती हैं। जिस प्रकार गर्मी के बाद वर्षा धरती को नई हरियाली देती है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयों के बाद भी सुख और शांति का नया अध्याय आता है।

आज आधुनिक जीवन में लोग सुख-समृद्धि पाने के लिए अनेक उपाय करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय सद्भाव, सेवा और श्रद्धा है। यदि घर में प्रेम हो, मन में भक्ति हो और व्यवहार में करुणा हो, तो वही सबसे बड़ी समृद्धि है। नौतपा के दिनों में किए गए छोटे-छोटे पुण्य कार्य मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। किसी जरूरतमंद को पानी पिलाना, पक्षियों के लिए दाना और जल रखना, गरीबों को फल बांटना या वृद्धजनों की सेवा करना—ये सभी कार्य ईश्वर की सच्ची पूजा माने गए हैं। पुराणों में कहा गया है कि सूर्य देव समस्त जगत के प्रत्यक्ष देवता हैं। वे बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सूर्य उपासना के साथ सेवा और दया का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में धीरे-धीरे अंधकार समाप्त होने लगता है। नौतपा का संदेश भी यही है कि तप के बीच करुणा को जीवित रखा जाए। जब बाहर की गर्मी बढ़े, तब भीतर का प्रेम और अधिक बढ़ना चाहिए। इन नौ दिनों को यदि केवल मौसम मानकर बिताया जाए, तो वे साधारण दिन बनकर निकल जाएंगे। लेकिन यदि इन्हें भक्ति, अनुशासन और सेवा के पर्व के रूप में अपनाया जाए, तो यही दिन जीवन में सुख, संतुलन और आत्मिक शांति का आधार बन सकते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर बड़े अनुष्ठानों से अधिक प्रसन्न सच्चे मन से किए गए छोटे कार्यों से होते हैं। इसलिए नौतपा के इन दिनों में श्रद्धा के साथ जल का सम्मान करें, सूर्य देव की आराधना करें और सेवा का भाव अपनाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में केवल सुख-समृद्धि ही नहीं आती, बल्कि मन में भी एक दिव्य शांति का अनुभव होने लगता है, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक मूल्यवान होती है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

VGRC का अगला पड़ाव होगा वड़ोदरा: मध्य गुजरात बनेगा औद्योगिक और पर्यटन विकास का नया ग्लोबल हब

- जून 2026 के अंतिम सप्ताह में वड़ोदरा में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) के 'मध्य गुजरात' संस्करण का होगा भव्य आयोजन
- राज्य के कुल विनिर्माण में 28% का योगदान देने वाले इस क्षेत्र ने 20.54 बिलियन डॉलर का किया है निर्यात
- इस सम्मेलन में सेमीकंडक्टर और फिनटेक जैसे आधुनिक उद्योगों के साथ-साथ पर्यटन विकास पर रहेगा विशेष फोकस
- मेहसाणा, राजकोट और सूरत संस्करणों में मिले ऐतिहासिक निवेश के बाद अब वड़ोदरा से नए रिकॉर्ड की है उम्मीद

गांधीनगर : वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की ऐतिहासिक सफलता और विरासत को आगे बढ़ाते हुए, राज्य सरकार अब क्षेत्रीय विकास को नई रफ्तार देने की तैयारी में है। इसी विज़न के तहत वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) का अगला भव्य आयोजन जून 2026 के अंतिम सप्ताह में वड़ोदरा में होने जा रहा है, जो मुख्य रूप से 'मध्य गुजरात' क्षेत्र पर केंद्रित होगा। अहमदाबाद, गांधीनगर, वड़ोदरा, आणंद, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद, छोटाउदेपुर, नर्मदा और महीसागर सहित 10 जिलों वाला यह क्षेत्र, राज्य के कुल विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) उत्पादन में 28% की मजबूत हिस्सेदारी रखता है।

औद्योगिक उत्पादन का पावरहाउस: विनिर्माण में मध्य गुजरात का दबदबा

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (2022-23) के आधिकारिक जिला-स्तरीय आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में इस क्षेत्र का असाधारण दबदबा नजर आता है। राज्य के कुल 'अन्य परिवहन उपकरण' (जिसमें रेलवे लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक, विमान, अंतरिक्ष यान, दोपहिया और तिपहिया वाहन आदि शामिल हैं) के विनिर्माण उत्पादन में मध्य गुजरात का योगदान अकेले 93% है। इसके अलावा, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स में 92%, पेय पदार्थों में 70%, तथा फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रिकल उपकरणों प्रत्येक में 63% का भारी योगदान इसी क्षेत्र से आता है।

निवेशकों के लिए यह क्षेत्र इसलिए भी सबसे आदर्श गंतव्य है क्योंकि गुजरात का लगभग 62% कुल क्षेत्रफल दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) के प्रभाव क्षेत्र में आता है। इस कॉरिडोर की प्रगति को गति देने के लिए मध्य गुजरात में दो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स विकास के विभिन्न चरणों में तेजी से आकार ले रहे हैं जिसमें 5,560 एकड़ में फैला धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेन्ट रीजन (DSIR) और 2,849 एकड़ का मांडल-बेचराजी स्पेशल इन्वेस्टमेन्ट रीजन (MBSIR) शामिल हैं।

हर जिले की अपनी विशिष्ट पहचान: पेट्रोकेमिकल से लेकर फिनटेक तक

मध्य गुजरात की सबसे बड़ी ताकत इसकी जिलावार औद्योगिक विविधता और विशेषज्ञता है। वड़ोदरा का रसायन और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र जिले के कुल विनिर्माण उत्पादन का 61% हिस्सा संभालता है। वहीं, अहमदाबाद ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स (18%), टेक्सटाइल (15%), बेसिक मेटल्स (13%) और फार्मास्यूटिकल्स (9%) में अग्रणी है। गांधीनगर का विनिर्माण उत्पादन मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग (18%), बेसिक मेटल्स (17%) और रसायनों (14%) द्वारा संचालित है। इसके साथ ही राज्य की राजधानी अपने शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग और 'गिफ्ट सिटी' की उपस्थिति के माध्यम से क्षेत्र के इलेक्ट्रॉनिक्स और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का नेतृत्व करती है।

दूसरी ओर, आणंद का विनिर्माण आधार मुख्य रूप से एग्रो और डेयरी प्रोसेसिंग (50%) तथा रसायनों (12%) पर टिका है। पंचमहाल अपनी ताकत ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स (23%), रबर और प्लास्टिक (19%) तथा फार्मास्यूटिकल्स (15%) सेक्टर से प्राप्त करता है, जबकि खेड़ा रबर और प्लास्टिक उत्पादों (23%) तथा फूड प्रोसेसिंग (22%) द्वारा संचालित है। जनजातीय और ग्रामीण बेल्ट में, नर्मदा के उत्पादन में फूड प्रोसेसिंग (92%) का पूर्ण दबदबा है, जबकि छोटाउदेपुर एग्रो और फूड प्रोसेसिंग (56%) तथा दाहोद फूड प्रोसेसिंग (48%) के माध्यम से इस विकास यात्रा में अपनी ठोस भागीदारी दर्ज करा रहे हैं।

ग्लोबल मार्केट में धमक: 20.54 बिलियन डॉलर का निर्यात

मध्य गुजरात की व्यावसायिक पहुँच अब दुनिया के नक्शे पर 219 से अधिक देशों तक फैल चुकी है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस क्षेत्र का कुल निर्यात 20.54 बिलियन डॉलर के जादुई आंकड़े को छू गया। इस निर्यात बास्केट में 3.67 बिलियन डॉलर (17.8%) की हिस्सेदारी के साथ फार्मास्यूटिकल्स सबसे आगे रहा। इसके बाद परमाणु रिएक्टर, बॉयलर और मशीनरी का योगदान 2.79 बिलियन डॉलर (13.6%), इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उपकरण 1.79 बिलियन डॉलर (8.7%), सड़क वाहन और पुर्जे 1.47 बिलियन डॉलर (7%), ऑर्गेनिक केमिकल्स 1.45 बिलियन डॉलर (7%), और रंगाई, टैनिंग व कलरिंग मैटर 1.03 बिलियन डॉलर (5%) का स्थान रहा। वैश्विक बाजारों में अमेरिका (USA) मध्य गुजरात के उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार बनकर उभरा है, जिसकी कुल निर्यात में 23.8% (4.88 बिलियन डॉलर) की हिस्सेदारी रही, जिसके बाद क्रमशः यूएई (7.3%), थाईलैंड (3%), यूके (2.8%), और सऊदी अरब (2.7%) का नंबर आता है।

भविष्य के सेक्टर्स और हेरिटेज टूरिज्म पर रहेगा विशेष फोकस

आगामी वीजीआरसी (मध्य गुजरात) में न केवल पारंपरिक उद्योगों, बल्कि भविष्य के हाई-टेक सेक्टर्स पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस सम्मेलन के फोकस क्षेत्रों में सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी और आईटीईएस, बायोटेक, फार्मास्यूटिकल्स, एयरोस्पेस और रक्षा, फिनटेक, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग, शिक्षा, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, वस्त्र और परिधान, ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम, कौशल विकास, स्टार्टअप्स, MSMEs, तथा पर्यटन और संस्कृति शामिल हैं।

इस सम्मेलन की एक और बड़ी विशेषता क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति देने के लिए 'पर्यटन और संस्कृति' को एक बड़े उत्प्रेरक के रूप में पेश करना है। हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद के गांधी आश्रम, वड़ोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस, गांधीनगर के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर और पंचमहाल स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 'चंपानेर-पावागढ़ पुरातत्व पार्क' के जरिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की बड़ी रणनीति है। विरासत से परे, यह क्षेत्र नर्मदा की विश्व प्रसिद्ध 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी', नलसरोवर पक्षी अभयारण्य और पावागढ़ हिल कॉरिडोर के माध्यम से इको-टूरिज्म और अनुभवात्मक यात्रा जैसी पहलों को भी बढ़ावा दे रहा है। साथ ही, गांधीनगर का महात्मा मंदिर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं की बदौलत यह क्षेत्र आकर्षक MICE यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसिंग और एग्जीबिशन पर्यटन का एक प्रमुख ग्लोबल हब बन रहा है।

VGRC बना निवेश का 'सुपरहिट' मॉडल: पिछले संस्करणों में टूटे कई रिकॉर्ड्स

VGRC का यह क्षेत्रीय फॉर्मेट निवेश जुटाने और वैश्विक भागीदारी का एक प्रामाणिक और बेहद सफल फॉर्मूला बन चुका है। 'विकसित भारत@2047' के लक्ष्यों के अनुरूप आयोजित हुए पिछले तीनों संस्करणों ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इस श्रृंखला की शुरुआत अक्टूबर 2025 में मेहसाणा में आयोजित उत्तर गुजरात के उद्घाटन संस्करण से हुई, जिसने 29,000 से अधिक पंजीकरणों और 80 से अधिक देशों के 440 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की ऐतिहासिक भागीदारी देखी, जिसके परिणामस्वरूप 3.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के साथ 1,264 एमओयू (MoUs) पर मुहर लगी। इसके बाद, जनवरी 2026 में राजकोट में आयोजित कच्छ और सौराष्ट्र संस्करण ने लगभग 29,000 पंजीकरणों और 57 देशों के करीब 400 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को आकर्षित किया, जिसके तहत 5.78 लाख करोड़ रुपये के भारी-भरकम निवेश प्रस्तावों वाले 5,492 एमओयू का एक नया रिकॉर्ड बना। इसी सफल कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, हाल ही में मई 2026 में सूरत में संपन्न दक्षिण गुजरात संस्करण ने भी 20,000 से अधिक पंजीकरणों और 27 देशों के 150 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की सक्रिय हिस्सेदारी के साथ 3.53 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश वाले 2,792 एमओयू को सफलतापूर्वक धरातल पर उतारा। इन लगातार ऐतिहासिक सफलताओं के बाद, अब देश-विदेश के निवेशकों की निगाहें वड़ोदरा में होने वाले इस आगामी महामंथन पर टिकी हैं, जो मध्य गुजरात को वैश्विक पटल पर विकास के एक नए रोल मॉडल के रूप में स्थापित करने जा रहा है।

'कोकरोच जनता पार्टी' का डिजिटल अभियान 6 दिनों में वायरल हो गया, सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट निलंबित कर दिए

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के एक बयान के विरोध में शुरू किया गया 'कोकरोच जनता पार्टी (सीजेपी)' नाम का डिजिटल अभियान महज 6 दिनों में इंटरनेट पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर इस पार्टी की खूब चर्चा हो रही है। कोकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट, जो महज 6 दिनों में इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है, कल भाजपा के फॉलोअर्स की संख्या को भी पार कर गया।

मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द 'तिलचट्टा' को कुछ लोगों ने गंभीरता से ले लिया और एक ऑनलाइन अभियान शुरू कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुख्य न्यायाधीश के फॉलोअर्स की संख्या 1.6 लाख से बढ़कर 1.4 करोड़ हो गई है। वहीं, इंस्टाग्राम पर भाजपा के फॉलोअर्स की संख्या मात्र 88 लाख है। चूंकि यह डिजिटल व्यंग्य खतरनाक रूप ले रहा है, इसलिए भारत सरकार ने कल मुख्य न्यायाधीश के सोशल मीडिया अकाउंट्स को निलंबित कर दिया। अब जब आप X पर मुख्य न्यायाधीश का अकाउंट खोलते हैं, तो लिखा होता है, "कानूनी मांग के कारण यह अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया गया है।"

यह विचार कैसे आया?

अभिजीत ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मैं सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस का बयान देख रहा था, जिसमें उन्होंने देश के युवाओं की तुलना तिलचट्टों और परजीवियों से करते हुए व्यवस्था की आलोचना की थी। मैंने सोशल मीडिया पर लोगों से पूछा कि अगर सारे तिलचट्टे एक साथ आ जाएं तो क्या होगा? मुझे जेनरेशन-जेड और 25 साल तक के युवाओं से चौंकाने वाले जवाब मिले। उन्होंने कहा कि हमें एक साथ आना चाहिए और एक मंच बनाना चाहिए। फिर मैंने तिलचट्टा जनता पार्टी (सीजेपी) का गठन किया।"

अभिजीत ने इस पार्टी की सदस्यता के लिए चार मानदंड भी प्रस्तुत किए हैं: बेरोजगारी, आलस्य, ऑनलाइन गपशप की लत और पेशेवर गुस्से को निकालने की क्षमता। उन्होंने इस पार्टी का लोगो भी डिजाइन किया है, जिसमें एक तिलचट्टा बना हुआ है। इस प्रकार, सीजेपी का पुराना खाता ब्लॉक कर दिया गया और एक नया खाता बनाया गया, जिसका नाम था "कॉकरोच इज़ बैक", और उसके नीचे टैगलाइन थी: "कॉकरोच कभी नहीं मरते"। यह नया खाता यह संदेश देता है कि कॉकरोच कभी नहीं मरते।

मांग में अभूतपूर्व वृद्धि के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तेल और गैस कंपनियों ने पेट्रोल डीजल और एलपीजी की आपूर्ति जारी रखी है

पीआईबी अहमदाबाद द्वारा 22 मई 2026 को शाम 8:24 बजे प्रकाशित।

गुजरात राज्य स्तरीय समन्वयक (एसएलसी) ने सूचित किया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) - इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल - राज्य और देश के कुछ क्षेत्रों में ईंधन की बढ़ती मांग के बीच पेट्रोल (एमएस), डीजल (एचएसडी) और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में परिचालन और लॉजिस्टिक्स समन्वय को लगातार बनाए रख रही हैं।

हाल के दिनों में, ओएमसी द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की निकासी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है:

एचएसडी (डीजल) – खुदरा बिक्री (1 से 21 मई)

राज्य	ज़िला	चालू वर्ष (सीवाई) मात्रा (किलोग्राम लीटर में)	पिछले वर्ष (LY) का आयतन (KL में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (% वृद्धि)
गुजरात	अहमदाबाद	44414	31990	39%
	आनंद	8717	5441	60%
	अरावली	7019	5227	34%
	बनासकांठा	23794	14383	65%
	गांधीनगर	11105	8330	33%
	खेड़ा	10098	7502	35%
	मेहसाणा	13426	8986	49%
	पाटन	6745	4765	42%
	साबरकांथा	8048	5284	52%
	वाव - थाराड	918	1306	42%
	अमरेली	8996	6630	36%
	भावनगर	12458	7828	59%
	नाव	3709	2071	79%
	देवभूमि द्वारका	5502	7361	34%
	गिर सोमनाथ	3509	6177	76%
	जामनगर	12104	8586	41%
	जूनागढ़	8924	5768	55%
	कच्छ	48378	27671	75%
	मोरबी	22354	18349	22%
	पोरबंदर	5327	3531	51%
	राजकोट	24367	15777	54%
	सुरेंद्रनगर	17746	12724	39%
	भरूच	19728	16635	19%
	छोटा उदेपुर	5389	3904	38%
	दाहोद	6247	4886	28%
	महासागर	2306	1754	31%
	नर्मदा	1941	1463	33%
	नवसारी	11568	9205	26%
	पंचमहल	7640	6511	17%
	सूरत	38172	29734	28%
	तापी	7653	5743	33%
	डैंग	727	502	45%
	वडोदरा	25440	17263	47%
	वलसाद	13342	12027	11%
	कुल गुजरात राज्य	452726	320399	41%

केंद्र शासित प्रदेश	ज़िला	चालू वर्ष (सीवाई) मात्रा (किलोग्राम लीटर में)	पिछले वर्ष (LY) का आयतन (KL में)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (% वृद्धि)
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	दीव	439	324	35%
	दादरा और नगर हवेली	7197	6097	18%
	दमन	3389	2790	21%
	कुल केंद्र शासित प्रदेश	11025	9211	20%

ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में जुताई और कटाई जैसी मौसमी गतिविधियों के कारण ईंधन की मांग में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के अलावा निजी आपूर्तिकर्ताओं के बीच मूल्य अंतर के कारण उपभोक्ता सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा आउटलेट (पेट्रोल पंप) की ओर और संस्थागत / वाणिज्यिक ग्राहक खुदरा ईंधन आउटलेट की ओर रुख कर रहे हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियां अपने व्यापक राष्ट्रव्यापी टर्मिनल नेटवर्क, डिपो, पाइपलाइन, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और खुदरा दुकानों के माध्यम से निर्बाध आपूर्ति बनाए रखती हैं। आपूर्ति दल, परिवहन नेटवर्क, टर्मिनल संचालन और चुनिंदा खुदरा दुकानें चौबीसों घंटे (24 घंटे) काम कर रही हैं ताकि उत्पादों की निर्बाध आवाजाही और बाजारों में समय पर आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियां ईंधन की निर्बाध आपूर्ति के लिए राज्य प्रशासन के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखती हैं।

तेल उद्योग उपभोक्ताओं को आश्वस्त करना चाहता है कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और सुचारू और निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सामान्य खरीदारी जारी रखें और घबराकर खरीदारी न करें। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे ईंधन की उपलब्धता के संबंध में सटीक जानकारी के लिए केवल अधिकृत एजेंसियों और तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

(रिलीज़ आईडी: 2264342) आगंतुकों की संख्या: 40

यह विज्ञप्ति पढ़ें: अंग्रेज़ी

सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ ने प्रतिपूर्ति प्रणाली का विरोध किया, 10 जून को धरने पर बैठने की धमकी दी

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ ने 18/05/2026 को सूरत नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की। वर्तमान में, नगर निगम के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बाहर से दवाइयां मंगाई जा रही थीं, जो अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थीं। ये दवाइयां मुफ्त में दी जा रही थीं। अब इस प्रथा को बंद कर दिया गया है और प्रतिपूर्ति प्रणाली शुरू कर दी गई है। यह प्रथा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों के खिलाफ है। इस प्रतिपूर्ति प्रणाली को बंद किया जाना चाहिए।

सूरत नगर निगम ने पुराने प्रस्ताव में संशोधन करते हुए एक परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कर्मचारी को पहले अपनी जेब से दवा खरीदनी होगी और तीन महीने बाद दवा का पैसा उनके वेतन में जमा कर दिया जाएगा। कुछ कर्मचारी और पेंशनभोगी इस समय गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं और उन्हें हर महीने 10,000 से 15,000 रुपये की दवा मिल रही है। वे अपनी पेंशन पर मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं और हर महीने इतना बड़ा खर्च वहन करना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए, पुरानी व्यवस्था ऐसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए वरदान साबित हुई थी। हम नगर निगम द्वारा इस व्यवस्था को बंद करके कर्मचारियों को कुचलने के इस कदम की कड़ी निंदा करते हैं।

हम मांग करते हैं कि सूरत नगर निगम इस परिपत्र को रद्द करे। इसके लिए 25/05/2026 को आवेदन दिया जाएगा। हालांकि, यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो हम 10/06/2026 को दोपहर 3 बजे सूरत नगर निगम के मुख्यालय के द्वार के पास धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे। सूरत नगर निगम कर्मचारी संघ ने सूरत नगर निगम के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। आज भाई लाल बी. वैष्णव के मुख्यालय में कर्मचारी संघ की बैठक हुई, जिसमें विभिन्न संघों के नेता सर्वश्री जयंतीभाई वाघेला, विजयभाई शेनमारे, शशिकांतभाई सोलंकी, मोहम्मद इकबाल शेख, किरीटभाई वाघेला, देवेंद्र प्रजापति और अन्य उपस्थित थे।

सप्ताह के दौरान सोना वायदा 2372 रुपये और चांदी वायदा 16219 रुपये लुढ़का: क्रूड ऑयल वायदा 8 रुपये नरम

मुंबई: देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर 15 से 21 मई के सप्ताह के दौरान कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 2660263.51 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 331916.87 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 2328344.66 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल साप्ताहिक प्रीमियम टर्नओवर 38654.45 करोड़ रुपये का हुआ।

आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 211105.05 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 160790 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 160992 रुपये और नीचे में 157547 रुपये पर पहुंचकर, 161978 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2372 रुपये या 1.46 फीसदी लुढ़ककर 159606 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। गोल्ड-गिनी मई वायदा सप्ताह के अंत में 2105 रुपये या 1.62 फीसदी गिरकर 127780 रुपये प्रति 8 ग्राम हुआ। गोल्ड-पेटल मई वायदा 266 रुपये या 1.64 फीसदी लुढ़ककर सप्ताह के अंत में 15999 रुपये प्रति 1 ग्राम बंद हुआ। सोना-मिनी जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 160003 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 160349 रुपये और नीचे में 157152 रुपये पर पहुंचकर, सप्ताह के अंत में 2448 रुपये या 1.52 फीसदी औंधकर 159005 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन मई वायदा प्रति 10 ग्राम सप्ताह के आरंभ में 159962 रुपये पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में ऊपर में 160620 रुपये और नीचे में 157159 रुपये पर पहुंचकर, 161664 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 2598 रुपये या 1.61 फीसदी गिरकर 159066 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ।

चांदी के वायदाओं में चांदी जुलाई वायदा सप्ताह के आरंभ में 280000 रुपये के भाव पर खूलकर, 283219 रुपये के उच्च और 264949 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 291102 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 16219 रुपये या 5.57 फीसदी की गिरावट के साथ 274883 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा चांदी-मिनी जून वायदा सप्ताह के अंत में 14893 रुपये या 5.07 फीसदी घटकर 278588 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो जून वायदा 14889 रुपये या 5.07 फीसदी गिरकर सप्ताह के अंत में 278594 रुपये प्रति किलो हुआ।

कमोडिटी वायदाओं में 331916 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 2328344 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ साप्ताहिक टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 211105 करोड़ रुपये का हुआ साप्ताहिक कारोबार

मेटल वर्ग में 36013.60 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मई वायदा सप्ताह के अंत में 40.4 रुपये या 2.92 फीसदी औंधकर 1345.05 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि जस्ता मई वायदा सप्ताह के अंत में 5 पैसे या 0.01 फीसदी के सुधार के साथ 367.45 रुपये प्रति किलो पर आ गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मई वायदा 1.25 रुपये या 0.32 फीसदी बढ़कर सप्ताह के अंत में 386.75 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ। जबकि सीसा मई वायदा सप्ताह के अंत में 40 पैसे या 0.2 फीसदी की नरमी के साथ 203.2 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 84786.45 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल जून वायदा सप्ताह के आरंभ में 9458 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 10150 रुपये के उच्च और 9211 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, सप्ताह के अंत में 8 रुपये या 0.09 फीसदी लुढ़ककर 9342 रुपये प्रति बैरल बंद हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी जून वायदा सप्ताह के अंत में 9 रुपये या 0.1 फीसदी गिरकर 9339 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ। इनके अलावा नैचुरल गैस मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 281 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के दौरान इंट्रा-डे में 303.4 रुपये के उच्च और 277.7 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 277.4 रुपये के पिछले बंद के सामने सप्ताह के अंत में 12.7 रुपये या 4.58 फीसदी की मजबूती के साथ 290.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू बंद हुआ। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मई वायदा सप्ताह के अंत में 12.7 रुपये या 4.58 फीसदी तेज होकर यह कॉन्ट्रैक्ट 290.1 रुपये प्रति एमएमबीटीयू पर आ गया।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मई वायदा सप्ताह के आरंभ में 994.5 रुपये के भाव पर खूलकर, सप्ताह के अंत में 9.2 रुपये या 0.93 फीसदी गिरकर 985.3 रुपये प्रति किलो हुआ।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर आलौच्य अवधि के सप्ताह के दौरान सोना के विभिन्न अनुबंधों में 101427.67 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 109677.38 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 27598.50 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 4239.52 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 103.27 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 3951.14 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 54086.50 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 30600.96 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 10.81 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई।

सप्ताह के अंत में ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 5799 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 35596 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 6309 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 82823 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 17242 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 9189 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19929 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 48953 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 14227 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 12420 लोट के स्तर पर था।

गिर सोमनाथ के बाद गुजरात में 7 और स्थानों पर लगाए जाएंगे 'स्टैटकॉम'

▸▸ 'स्मार्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर' के रूप में जाना जाने वाला यह सिस्टम ग्रिड में वोल्टेज के उतार-चढ़ाव की समस्या को दूर करता है

▸▸ 'गेटको' भारत में 'स्टैटकॉम' टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली पहली स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी

▸▸ 'स्टैटकॉम' से कृषि क्षेत्र में वोल्टेज स्थिरता और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हुई

गांधीनगर : एक समय बिजली की कमी वाला गुजरात राज्य आज देश में ऊर्जा क्षेत्र में एक अग्रणी और आत्मनिर्भर राज्य बन गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विद्युत क्षेत्र में किए गए व्यापक सुधार के परिणास्वरूप राज्य में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हुई। उनके नेतृत्व में ही गांवों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए ज्योतिग्राम योजना शुरू की गई, जो अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन गई है। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात विद्युत क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने गिर सोमनाथ जिले के टिंबड़ी सबस्टेशन में राज्य का पहला अत्याधुनिक 'स्टैटिक सिंक्रोनस कम्पेनसेटर' (STATCOM - स्टैटकॉम) स्थापित करके पावर ग्रिड को अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया। आने वाले समय में राज्य के 7 महत्वपूर्ण सबस्टेशनों पर भी स्टैटकॉम लगाने की योजना है।

गुजरात का पहला स्टैटकॉम गिर सोमनाथ जिले में

गुजरात सरकार के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के अंतर्गत कार्यरत गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (GETCO – गेटको) द्वारा अद्यतन स्टैटिक सिंक्रोनस कम्पेनसेटर स्थापित किया गया है। 'स्मार्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर' के रूप में जाना जाने वाला यह सिस्टम ग्रिड में वोल्टेज स्थिरता और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही ग्रिड में किसी भी बदलाव की स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया भी देता है।

5 मार्च, 2019 को गिर सोमनाथ जिले के 220 केवी टिंबड़ी सबस्टेशन में 120 एमवीएआर (मेगा वोल्ट एम्पीयर रिऐक्टिव) क्षमता वाला स्टैटकॉम कार्यरत हुआ। इसके साथ ही, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (गेटको) भारत में स्टैटकॉम टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली पहली स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी बन गई है।

क्यों पड़ी स्टैटकॉम की जरूरत?

गुजरात में विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर कृषि क्षेत्र में बिजली की मांग अधिक रहती है, जिससे ग्रिड में वोल्टेज की स्थिरता और बिजली की गुणवत्ता को बनाए रखना एक चुनौती बन जाती है। परंपरागत कैपेसिटर और रिएक्टर जैसी व्यवस्थाएं स्थिर सपोर्ट तो देती हैं, लेकिन मांग में होने वाले उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए एक विशेष सिस्टम की जरूरत थी। टिंबड़ी सबस्टेशन में सिंगल-सर्किट लिंक और आसपास विद्युत उत्पादन स्रोत के अभाव के कारण वोल्टेज में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता था। विशेषकर कृषि में बिजली की अधिक मांग होने के कारण वोल्टेज का स्तर 190 केवी से 245 केवी के बीच रहता था। पीक समय के दौरान वोल्टेज 190-200 केवी तक गिर जाता था। वहीं, मानसून के दौरान जब मांग कम होती है, तब 235-245 केवी तक बढ़ जाता था। इस परिस्थिति में वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए ऐसा डायनामिक सिस्टम शुरू किया गया, जो वोल्टेज स्थिरता और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करता है।

स्टैटकॉम ग्रिड की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए तुरंत प्रतिक्रिया देता है। यह आवश्यकतानुसार रिएक्टिव पावर प्रदान या अवशोषित करके वोल्टेज को स्थिर रखता है। रियल-टाइम में काम करने वाला यह सिस्टम अलग-अलग लोड पर भी ग्रिड को संतुलित रखता है, पावर फैक्टर को नियंत्रित करता है, ओवर-वोल्टेज कम करता है और वोल्टेज के अचानक गिरने की स्थिति को रोकता है। इससे ट्रांसमिशन सिस्टम पर दबाव कम हुआ है, बिजली का नुकसान कम हुआ है और उपकरणों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई है। इस सिस्टम से गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली और आसपास के क्षेत्रों में विशेषकर किसानों को लाभ हुआ है। इसके साथ ही, ग्रामीण और औद्योगिक, दोनों प्रकार की जरूरतों के लिए विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हुई है।

टिंबड़ी में मिली सफलता के बाद गुजरात सरकार ने अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी स्टैटकॉम स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके तहत छह मौजूदा 220 केवी सबस्टेशनों- थराद, दियोदर, सागपरा, खेरालु, कुकमा और ध्रांगध्रा और आगामी 400 केवी धोलेरा-2 सबस्टेशन में 125 एमवीएआर क्षमता वाले स्टैटकॉम स्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह पहल राज्य के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत करेगी और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।

कच्छ से देश की राजधानी दिल्ली के लिए नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ

माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिखाई हरी झंडी

रेल यात्रियों की सुविधा को सर्वोपरि रखते हुए तथा कच्छ क्षेत्र को देश की राजधानी दिल्ली से सीधे एवं बेहतर रेल संपर्क प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आज दिनांक 22 मई, 2026 को भुज एवं दिल्ली के बीच नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया गया। गाड़ी संख्या 19403/19404 भुज–दिल्ली–भुज एक्सप्रेस का उद्घाटन माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव एवं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर किया गया।

इस अवसर पर माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज़ादी के बाद से भुज–जालोर–पाली क्षेत्र को दिल्ली के साथ सीधी रेल कनेक्टिविटी देने का सपना आज साकार हुआ है। उन्होंने बताया कि देशभर में 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा रेलवे के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित किया गया है, जिसके अंतर्गत गुजरात में 4600 करोड़ रुपये के निवेश से 85 स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, जिनमें से 15 स्टेशनों का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त 24 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनलों का निर्माण किया जा रहा है तथा 14,000 करोड़ रुपये के निवेश से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर का कार्य भी पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि तारंगा हिल–अंबाजी रेल लाइन का कार्य भी तीव्र गति से प्रगति पर है तथा इसका पहला खंड दिसंबर माह में प्रारंभ किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि वर्तमान में भुज–बरेली साप्ताहिक ट्रेन सेवा संचालित की जा रही है, जिसमें लगभग 80 प्रतिशत यात्री बरेली एवं उत्तर भारत क्षेत्र के होते हैं। नई भुज–दिल्ली एक्सप्रेस के प्रतिदिन संचालन से यात्रियों को अधिक सुविधाजनक, नियमित एवं बेहतर रेल सेवा उपलब्ध होगी।

माननीय रेल मंत्री ने आगे कहा कि नई भुज–दिल्ली एक्सप्रेस से गुजरात के 6 शहरों तथा अन्य 19 शहरों को दिल्ली से सीधी रेल कनेक्टिविटी प्राप्त होगी। इस ट्रेन सेवा से विद्यार्थियों, श्रमिकों, हस्तशिल्प उद्योग से जुड़े कारीगरों, व्यापारियों, उद्योग जगत एवं किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि रणोत्सव के दौरान दिल्ली एवं उत्तर भारत के यात्रियों को कच्छ आने के लिए प्रतिदिन सीधी ट्रेन सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

इस अवसर पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारतीय रेल का अभूतपूर्व कायाकल्प हुआ है। उन्होंने बताया कि हाल ही में अहमदाबाद–धोलेरा सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना की सौगात भी गुजरात को मिली है। उन्होंने कहा कि 'मेक इन इंडिया' के अंतर्गत निर्मित वंदे भारत एवं नमो भारत रैपिड रेल जैसी आधुनिक ट्रेनों ने न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान की है, बल्कि देश के विकास को भी नई गति दी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का कार्य गुजरात में तीव्र गति से चल रहा है तथा 508 किलोमीटर लंबी परियोजना में से 348 किलोमीटर का निर्माण गुजरात में हो रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 के बजट में गुजरात को रिकॉर्ड 17,366 करोड़ रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो वर्ष 2014 की तुलना में लगभग 29 गुना अधिक है। वर्तमान में गुजरात राज्य में 1,28,748 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न रेल परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 12 वर्षों में गुजरात के सभी रेलवे मार्गों का 100% विद्युतीकरण किया गया है।

इस अवसर पर भुज स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में श्री त्रिकमभाई छांगा, माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री, गुजरात सरकार एवं माननीय विधायक – अंजार, माननीय सांसद (कच्छ) श्री विनोद एल. चावड़ा, माननीय विधायक (भुज) श्री केशुभाई शिवदास पटेल, श्री प्रद्युम्नसिंह जाडेजा, माननीय विधायक – अबडासा, पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय, मंडल रेल प्रबंधक अहमदाबाद श्री वेद प्रकाश सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

नई दैनिक ट्रेन सेवा के शुभारंभ से कच्छ क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली के लिए सीधी रेल सुविधा उपलब्ध हो गई है। यह ट्रेन गुजरात एवं राजस्थान के विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों एवं स्टेशनों को जोड़ते हुए यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करेगी।

गाड़ी संख्या 19403/19404 भुज–दिल्ली–भुज एक्सप्रेस

गाड़ी संख्या 19403 भुज–दिल्ली एक्सप्रेस 23 मई 2026 से प्रतिदिन भुज से 11:15 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 11:45 बजे दिल्ली पहुंचेगी।

इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 19404 दिल्ली–भुज एक्सप्रेस 24 मई 2026 से प्रतिदिन दिल्ली से 16:40 बजे प्रस्थान कर अगले दिन 19:35 बजे भुज पहुंचेगी।

मार्ग में प्रमुख ठहराव

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में अंजार, गांधीधाम, भचाऊ, भीलड़ी, धानेरा, रानीवाड़ा, मारवाड़ भीनमाल, मोदरान, जालोर, मोकलसर, समदड़ी, लूणी, पाली मारवाड़, मारवाड़ जंक्शन, ब्यावर, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, गांधी नगर-जयपुर, बांदीकुई, अलवर एवं रेवाड़ी स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में 2-टियर एसी, 3-टियर एसी, स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच उपलब्ध रहेंगे।

इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा भुज से हरिद्वार के लिए सीधी ट्रेन सेवा प्रारंभ करने की मांग भी रखी गई, जिस पर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय ने सकारात्मक विचार करने एवं आवश्यक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।

भावनगर मंडल की तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें अब नियमित रूप से चलेंगी

यात्रियों की सुविधा, उनकी बढ़ती मांग एवं ट्रेनों को मिल रहे उत्कृष्ट प्रतिसाद को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड द्वारा पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल की तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को अब जून, 2026 से नियमित ट्रेनों के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं प्रयासों से संभव हुआ है।

इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि इन ट्रेनों के नियमित संचालन से यात्रियों को पूर्व नियोजन में सुविधा होगी तथा किराए में कमी के कारण किफायती यात्रा का लाभ प्राप्त होगा। ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है:-

ट्रेन नंबर 09529/09530 धोला-भावनगर टर्मिनस दैनिक स्पेशल अब ट्रेन नंबर 59239/59240 धोला-भावनगर दैनिक पैसेन्जर के रूप में चलेगी। ट्रेन नंबर 59239 धोला-भावनगर टर्मिनस दैनिक पैसेन्जर धोला स्टेशन से 11.30 बजे प्रस्थान कर 12.50 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन नंबर 59240 भावनगर टर्मिनस दैनिक पैसेन्जर भावनगर टर्मिनस से 13.15 बजे प्रस्थान कर 14.35 बजे धोला पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में सणोसरा, बजुड, सोनगढ़, सिहोर (गुजरात), खोडीयार मंदिर, वरतेज एवं भावनगर परा स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रूकेगी। इन दोनों ट्रेनों के लिए यह परिवर्तन 01 जून 2026 से प्रभावी होगा।

ट्रेन नंबर 09215/09216 गांधीग्राम-भावनगर टर्मिनस दैनिक स्पेशल अब ट्रेन नंबर 59231/59232 गांधीग्राम-भावनगर टर्मिनस दैनिक पैसेन्जर के रूप में चलेगी। ट्रेन नंबर 59231 गांधीग्राम-भावनगर टर्मिनस दैनिक पैसेन्जर गांधीग्राम से 06.35 बजे प्रस्थान कर 11.25 बजे भावनगर टर्मिनस पहुंचेगी। यह परिवर्तन 02.06.2026 से प्रभावी होगा। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन नंबर 59232 भावनगर टर्मिनस-गांधीग्राम दैनिक पैसेन्जर भावनगर टर्मिनस से 17.00 बजे प्रस्थान कर 21.55 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी। यह परिवर्तन 01.06.2026 से प्रभावी होगा। यह ट्रेन मार्ग में वस्त्रापुर, सरखेज, बावला, धोलका, धंधुका, बोटाद, धोला, सिहोर (गुजरात) एवं भावनगर परा स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रूकेगी। ट्रेन नंबर 09211/09212 गांधीग्राम-बोटाद दैनिक स्पेशल अब ट्रेन नंबर 59237/59238 गांधीग्राम-बोटाद दैनिक पैसेन्जर के रूप में चलेगी। ट्रेन नंबर 59237 गांधीग्राम-बोटाद दैनिक पैसेन्जर गांधीग्राम से 09.15 बजे प्रस्थान कर 13.30 बजे बोटाद पहुंचेगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन नंबर 59238 बोटाद-गांधीग्राम दैनिक पैसेन्जर बोटाद से 14.05 बजे प्रस्थान कर 18.05 बजे गांधीग्राम पहुंचेगी। यह ट्रेन मार्ग में वस्त्रापुर, सरखेज, मोरैया, मटोडा, बावला, धोलका, गोधनेश्वर, कोठ गांगड, अरणेज, लोथल भुरखी, लोलीया, हडाला भाल, धोली भाल, रायका, धंधुका, तगडी, भीमनाथ, चंदरवा, जालिला रोड, सारंगपुर रोड एवं अलाऊ स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में रूकेगी। इन दोनों ट्रेनों के लिए यह परिवर्तन 01.06.2026 से प्रभावी होगा। मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने कहा कि यह निर्णय यात्रियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, जिससे उन्हें नियमित, सुलभ एवं किफायती रेल सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

रूसी संघ के मुंबई स्थित महावाणिज्य दूत श्री इवान फेतिसोव ने गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की

▸▸ गुजरात के साथ मैरीटाइम, शिप बिल्डिंग तथा एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में सहभागिता के लिए तत्परता दर्शाई

▸▸ मुख्यमंत्री को रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाली बिजनेस समिट में सहभागी होने का आमंत्रण दिया

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने का निमंत्रण दिया

गांधीनगर : रूसी संघ के मुंबई स्थित महावाणिज्य दूत श्री इवान फेतिसोव ने शुक्रवार को गांधीनगर में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री के साथ आयोजित इस बैठक में रूसी महावाणिज्य दूत ने गुजरात के साथ विशेषकर मैरीटाइम, शिप बिल्डिंग तथा एजुकेशन सेक्टर्स में सहभागिता एवं समन्वय के लिए तत्परता दर्शाई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पृष्ठभूमि दी कि गुजरात के पास देश में सबसे विशाल समुद्री तट है और गुजरात ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशा-दर्शन में पोर्ट लेड डेवलपमेंट की नई परंपरा विकसित की है। श्री पटेल ने विचार-विमर्श के दौरान यह भी कहा कि देश की 40 प्रतिशत कारगो हैंडलिंग गुजरात के बंदरगाहों से होती है।

मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इतना ही नहीं; शिप रिसाइकलिंग तथा शिप बिल्डिंग में भी गुजरात ने अग्रसरता प्राप्त की है और गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न सेक्टर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटियों से गुजरात मॉडर्न एजुकेशन हब बनने के लिए सज्ज है।

रूसी संघ के महावाणिज्य दूत श्री इवान ने उल्लेख किया कि रूस वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में पार्टनर कंट्री रहा था और हाल ही में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टनर ऑर्गेनाइजर के रूप में सहभागी हुआ था।

उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आगामी समय में आयोजित होने वाली बिजनेस समिट में भाग लेने का आमंत्रण दिया।

मुख्यमंत्री ने भी वाइब्रेंट समिट की आगामी कड़ी में रूस के प्रतिनिधिमंडल को सहभागी होने का निमंत्रण दिया।

इस शिष्टाचार भेंट तथा बैठक में उद्योग विभाग की अपर मुख्य सचिव श्री ममता वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) की प्रबंध निदेशक श्री प्रवीणा डी. के. तथा इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो (इंडेक्स्ट-बी) के संयुक्त प्रबंध निदेशक श्री अमित प्रकाश यादव भी सहभागी हुए।

फियो ने वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल की कनाडा यात्रा का स्वागत किया; भारत-कनाडा सीईपीए वार्ता के लिए सकारात्मक प्रगति की संभावना व्यक्त की

नई दिल्ली, 22 मई, 2026: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन्स (फियो) ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की 25-27 मई, 2026 तक कनाडा की आगामी यात्रा का स्वागत किया है। फियो इसे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानता है। यह यात्रा ऐसे समय में विशेष महत्व रखती है जब भारत और कनाडा प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) पर बातचीत को फिर से शुरू करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसका एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ाना है।

इस घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए, फियो के अध्यक्ष श्री एस.सी. रल्हन ने कहा कि फियो माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की कनाडा यात्रा का पुरजोर स्वागत करता है। यह यात्रा आर्थिक जुड़ाव को फिर से बनाने और प्रस्तावित सीईपीए पर चर्चा को तेज करने के लिए दोनों राष्ट्रों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारत और कनाडा कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, खाद्य प्रसंस्करण, शिक्षा और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में एक-दूसरे के पूरक हैं, जो द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं।

श्री रल्हन ने आगे कहा कि प्रस्तावित व्यापार समझौता भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई के लिए नए अवसर खोलेगा। यह बाजार तक पहुंच में सुधार करके, व्यापार प्रक्रियाओं को सुगम बनाकर और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार-संचालित क्षेत्रों में अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करके ऐसा करेगा। बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य और आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्संरेखण के बीच, भारत-कनाडा के मजबूत व्यापारिक संबंध दोनों देशों के लिए आर्थिक लचीलेपन और विकास में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं।

फियो ने उल्लेख किया कि भारत और कनाडा के बीच यह नया जुड़ाव एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है जब वैश्विक बाजार भू-राजनीतिक संघर्षों, टैरिफ-संबंधी व्यवधानों और बदलते अंतरराष्ट्रीय व्यापार गठबंधनों से उत्पन्न अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं। यह उम्मीद की जाती है कि बढ़ा हुआ द्विपक्षीय सहयोग व्यापारिक साझेदारियों के विविधीकरण का समर्थन करेगा और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा को मजबूत करेगा।

शीर्ष निर्यातक निकाय ने दोनों देशों के बीच मंत्री-स्तरीय आदान-प्रदान और व्यापार मिशनों में बढ़ती गति को भी रेखांकित किया, जिसमें भारतीय और कनाडाई व्यापार अधिकारियों के बीच हालिया जुड़ाव भी शामिल हैं। फियो का मानना है कि निरंतर संवाद और उद्योग-स्तरीय सहयोग विश्वास बहाल करने और द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फेडरेशन ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री की यात्रा सीईपीए वार्ताओं को नई गति प्रदान करेगी और भारत तथा कनाडा के बीच गहन आर्थिक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी।

पश्चिम रेलवे मुख्यालय में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक सम्पन्न

केंद्रीय सरकारी कार्यालयों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), मुंबई की वर्ष 2026 की प्रथम छमाही बैठक 21 मई, 2026 को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री रामाश्रय पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक के दौरान नराकास, मुंबई द्वारा आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के 20 विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए तथा प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका निभाने वाले 7 अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही, वर्ष 2025-26 में राजभाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन सदस्य कार्यालयों – मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, मुंबई सेंट्रल; निदेशक, भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, महालक्ष्मी, मुंबई; तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, लोअर परेल, मुंबई – को राजभाषा शील्ड एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर नराकास, मुंबई की गृह पत्रिका 'राजभाषा प्रवाह' का भी अध्यक्ष महोदय द्वारा विमोचन किया गया।

राजभाषा के प्रचार-प्रसार में पश्चिम रेलवे हमेशा से अग्रणी रहा है। इसकी सार्थकता को देखते हुए पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक श्री के. पद्मनाथन द्वारा लिखित काव्य-संग्रह 'रुक जाना नहीं.....' का विमोचन भी बैठक के दौरान अध्यक्ष एवं महाप्रबंधक महोदय द्वारा किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने पुरस्कृत सभी कर्मियों को शुभकामनाएं दीं और समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय सरकारी कार्यालयों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राजभाषा के प्रचार-प्रसार और प्रयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना एक राष्ट्रीय कार्य है, क्योंकि भारत की आम जनता हिंदी को अच्छी तरह समझती है और इसका प्रयोग करती है। भारतीय संविधान निर्माता यह अच्छी तरह जानते थे कि भाषा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की संवाहिका होती है और राष्ट्र की एकता और अखंडता में एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। इसलिए भारतीय संविधान में हिंदी को 'राजभाषा' के रूप में स्वीकार किया गया है। कार्यालय प्रमुख स्वयं हिंदी में कार्य करेंगे तो स्वतः ही राजभाषा का प्रचार-प्रसार बढ़ेगा और अन्य अधिकारी/कर्मचारी भी अपना अधिकांश कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित होंगे। उन्होंने सभी कार्यालयों से अनुरोध किया कि वे अपने कार्यालय की वेबसाइट निश्चित रूप से चेक करें। राजभाषा नियमानुसार वे द्विभाषी में होनी चाहिए और समय-समय पर जो सामग्री उनमें अपलोड की जाती हैं, वे भी द्विभाषी में हों और कार्यालय की वेबसाइट डिफॉल्ट रुप से हिंदी में ही खुले।

बैठक के प्रारंभ में पश्चिम रेलवे के मुख्य राजभाषा अधिकारी विनीत गुप्ता ने अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि वास्तव में किसी भी समाज, राष्ट्र और सभ्यता की पहचान उसकी अपनी भाषा से होती है। हिंदी भारत की विभिन्न संस्कृतियों, कलाओं, भाषाओं, विधाओं और सम्प्रदायों को एक कड़ी में जोड़ती है। हिंदी ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में भी देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज भी संपर्क भाषा के रुप में आम जनता के आपसी विचारों के आदान-प्रदान में विशेष योगदान दे रही है।

इस बैठक में मुंबई स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में अक्टूबर-2025 से मार्च-2025 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में समिति के सभी सदस्य कार्यालयों में अक्टूबर-2025 से मार्च-2025 के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति संबंधी आंकड़ों को समिति की सदस्य सचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया और राजभाषा कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की गई और कार्यालयों में राजभाषा को लागू करने के लिए कई सार्थक एवं नीतिगत निर्णय लिये गये।

बैठक में प्रधान कार्यालय-मध्य रेल, मुंबई सेंट्रल मंडल-पश्चिम रेलवे, भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, कर्मचारी राज्य बीमा आयोग, भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग (लेखा व हकदारी), मुंबई, प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (नौवहन), मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, बेलापुर आदि केंद्र सरकार के कार्यालयों के विभागाध्यक्ष एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक का संचालन एवं समापन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी श्रीमती सुनीता अहिरे के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

पश्चिम रेलवे मुंबई एवं गोरखपुर के बीच चलाएगी स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा ग्रीष्मकालीन सीजन के दौरान उनकी यात्रा मांग को पूरा करने के उद्देश्य मुंबई एवं गोरखपुर के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रेन संख्या 09157 बांद्रा टर्मिनस – गोरखपुर स्पेशल रविवार, 24 मई, 2026 को 00:30 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 17:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09158 गोरखपुर – बोरीवली स्पेशल सोमवार, 25 मई, 2026 को 20:30 बजे गोरखपुर से प्रस्थान करेगी तथा बुधवार को 11:30 बजे बोरीवली पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 09157/09158 बांद्रा टर्मिनस–गोरखपुर-बोरीवली स्पेशल मार्ग में बोरीवली, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, बयाना, भरतपुर, मथुरा, हाथरस सिटी, कासगंज, बरेली सिटी, इज्जतनगर, पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर, बुढ़वल, गोंडा, बस्ती एवं खलीलाबाद स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में शयनयान एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09157 के विस्तारित फेरों की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों तथा IRCTC वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव समय एवं रेक संरचना संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की वर्चुअल उपस्थिति में कच्छ को नई दिल्ली से जोड़ने वाली सीधी रेल सेवा का शुभारंभ हुआ

▸▸ केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भुज-दिल्ली ट्रेन के प्रस्थान में राजस्थान के पाली से वर्चुअल माध्यम द्वारा सहभागी हुए

▸▸ भारतीय रेलवे परिवहन की महत्वपूर्ण कड़ी है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले बारह वर्षों में इसका बड़े पैमाने पर कायाकल्प हुआ है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में गुजरात ने आधुनिक रेलवे क्रांति में लीड ली है

▸▸ देश की पहली बुलेट ट्रेन का काम पूरे जोश में चल रहा है

▸▸ 2014 के बाद गुजरात में 2900 किलोमीटर नए ट्रैक का निर्माण हुआ

▸▸ 2026-27 में रेलवे बजट में गुजरात को 17366 करोड़ रुपए मिले

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की गांधीनगर से तथा केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की राजस्थान के पाली से वर्चुअल उपस्थिति में शुक्रवार को भुज से दिल्ली के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन का प्रारंभ हुआ।

मुख्यमंत्री ने कच्छ को नई दिल्ली से जोड़ने वाली सीधी रेल सेवा की भेंट तथा हाल ही में अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई स्पीड प्रोजेक्ट की मंजूरी की भेंट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि भारतीय रेल परिवहन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप में पिछले बारह वर्षों में बड़े पैमाने पर रेलवे का कायाकल्प हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि गुजरात ने इस हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के माध्यम से आधुनिक रेलवे क्रांति में लीड ली है। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 348 किलोमीटर गुजरात की धरती पर निर्मित हो रहा है।

उन्होंने गुजरात में रेलवे नेटवर्क के विकास की गति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में और अधिक गतिशील बनी है, इसकी विस्तृत भूमिका प्रस्तुत की।

इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 के बाद राज्य में 2900 किलोमीटर नए ट्रैक का निर्माण हुआ है। इसके अलावा राज्य में 1 लाख 28 हजार करोड़ रुपए के विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट कार्यरत हैं।

उन्होंने जोड़ा कि 2014 की तुलना में इस वर्ष 29 प्रतिशत अधिक राशि अर्थात 17366 करोड़ रुपए की राशि गुजरात को रेलवे बजट के अंतर्गत आवंटित की गई है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने गुजरात को पांच वंदे भारत, एक अमृत भारत और एक नमो भारत ट्रेन की भेंट देने के साथ विश्व के अग्रणी पर्यटन स्थल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक यात्रियों को आसानी से पहुंचाने के लिए एकता नगर को रेलवे सेवाओं की कनेक्टिविटी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और रेल मंत्री के मार्गदर्शन में आजादी का यह अमृतकाल रेलवे को नई गति देने वाला और विकसित भारत के निर्माण का काल बनेगा। भुज-दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन को भुज रेलवे स्टेशन से रवाना करने के इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री त्रिकमभाई छांगा, सांसद श्री विनोदभाई चावडा, कच्छ जिले के विधायक, पदाधिकारी, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी तथा नागरिक उत्साहपूर्वक सहभागी हुए।